



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042025-262646
CG-DL-E-24042025-262646

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2025/ वैशाख 2, 1947

No. 125]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2025/ VAISAKHA 2, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2025

मामला सं.-एडीडी (एसएसआर) -03/2024

विषय: चीन जन.गण. से एनिलिन के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम।

फा.सं. 7/10/2024-डीजीटीआर—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे “नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” कहा गया है) को गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जिन्हें आगे “आवेदक” अथवा “घरेलू उद्योग” कहा गया है) से एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन.गण (जिसे यहां आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एनिलीन (जिसे यहां आगे “संबद्ध सामान” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने के लिए निर्णायक समीक्षा शुरू करने की मांग की गई थी।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयात में मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा 24 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी। आवेदक के अनुरोध और पूरी प्रारंभिक जांच के बाद, प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/42/2019-डीजीटीआर, दिनांक 12 जून 2020 के माध्यम से अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की। उसके बाद वित्त मंत्रालय ने दिनांक 29 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. 20/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए।
2. अंतिम जांच परिणाम संख्या 6/42/2019-डीजीटीआर, दिनांक 20 जनवरी 2021 के माध्यम से, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम की पुष्टि की और 5 साल की अवधि के लिए उपाय लागू करने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 08/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 19 फरवरी 2021 के द्वारा शुल्क लगाया।
3. इसके बाद प्रयोक्ता उद्योग के अनुरोध पर एक मध्यावधि समीक्षा शुरू की गई ताकि यह जांच की जा सके कि क्या चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने फा. संख्या 7/25/2022-डीजीटीआर दिनांक 11 दिसंबर 2023 के तहत निष्कर्ष निकाला कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता थी। वर्तमान उपाय 28 जुलाई 2025 तक लागू हैं।
4. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया कोई भी पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता है, ऐसे लगाए जाने की तारीख से पांच साल की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

“.....किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत् पुष्टि; तथा अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।”

5. उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करनी होगी कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।
6. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/10/2024- डीजीटीआर दिनांक 24 सितंबर 2024 के

माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की। यह जांच नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार शुरू की गई थी ताकि यह जांच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग के लिए पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता है।

7. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में अंतिम जांच परिणाम संख्या 06/42/2019-डीजीटीआर दिनांक 20 जनवरी 2021 और अधिसूचना संख्या 08/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 19 फरवरी 2021 के सभी पहलु शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

8. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 24 सितंबर, 2024 की अधिसूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल पत्तों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 24 सितंबर, 2024 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी।
- घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
- ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी उन्हें संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पत्तों के साथ भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:
- छ. वर्तमान जांच में निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने पंजीकरण कराया है:

क्र.स.	संबद्ध देश में उत्पादक/निर्यातक का नाम
1	वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्रा.लि.
2	वानहुआ केमिकल ग्रुप कं.लि.
3	वानहुआ केमिकल (यंताई) ट्रेडिंग कं.लि.
4	केम्पार एनर्जी प्रा.लि.
5	कॉनेल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी

6	जिलिन रिसुन कॉनेल केमिकल कं.लि.
7	रिसुन मार्केटिंग लिमिटेड

- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए, भारत में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी।
- झ. वर्तमान जांच में निम्नलिखित प्रयोक्ताओं/आयातकों ने पंजीकरण कराया है।

क्र.सं.	प्रयोक्ताओं और आयातकों के नाम
1	एनओसीआईएल लिमिटेड
2	आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- ञ. प्राधिकारी ने ज्ञात एसोसिएशन को भी जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रतियां भेजीं तथा उनकी टिप्पणियां मांगीं।
- ट. जिन विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है, या इस जांच से संगत सूचना नहीं दी है, उन्हें असहयोगी माना गया है।
- ठ. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। आर्थिक हित प्रश्नावली केवल घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई थी। अन्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली दायर नहीं की है।
- ड. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।
- ढ. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (12 महीने की अवधि) है। जांच के लिए क्षति अवधि में 2020-21, 2021-22, 2022-23 की अवधि और जांच की अवधि शामिल है।
- ण. आयात आंकड़ों के लिए सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हो गए और उन्होंने लेनदेनों की जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- त. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 13 मार्च 2025 को हाइब्रिड मोड में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई के दौरान अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें, उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि

- कोई हों, दायर करें। पक्षकारों ने अपने अगोपनीय अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किए तथा उन्हें अपने खंडन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।
- थ. नियम 6(8) के अनुसार, जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा समय पर उपलब्ध नहीं कराई है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए हैं।
- द. क्षति रहित कीमत (जिसे यहां आगे “एनआईपी” कहा गया है) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और उपयुक्त लाभ के आधार पर निर्धारित की गई
- ध. नियम 8 के अनुसार, जांच प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की प्रशुद्धता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया, जो इस अंतिम जांच परिणाम का आधार बनती है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और दस्तावेजों को संगत, व्यावहारिक और आवश्यक मानी गई सीमा तक सत्यापित किया।
- न. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच उन गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करें।
- प. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने इससे इंकार किया है, अथवा अन्यथा वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- फ. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और दी गई सूचना पर इस सीमा तक विचार किया है कि जहां तक वे वर्तमान जांच में साक्ष्यों और संगत मानी गई सीमा तक समर्थित हैं प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम के बाद हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संबंधी दस्तावेजों की आगे जांच करेंगे, जो अंतिम जांच परिणामों के निष्कर्षों के लिए आधार बनेगी।
- ब. इस जांच में आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण, जो वर्तमान अंतिम जांच परिणाम का आधार बनता है, हितबद्ध पक्षकारों को 9 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात विवरण अनुरोधों पर, इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में, संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- भ. इस अंतिम जांच परिणाम में “****” हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- म. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर एक यूएसडॉ.=83.69 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध:

10. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निम्नानुसार निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है।
- ख. एनिलिन, जिसे फेनिलमाइन या एमिनोबेन्जीन के रूप में भी जाना जाता है, एक मौलिक सुगंधित अमाइन है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, रंगों और रंग मध्यवर्ती पदार्थों में किया जाता है।
- घ. विचाराधीन उत्पाद कोड 29214110 के तहत अध्याय 29 में वर्गीकृत है।
- ड. उत्पाद में कोई विकास नहीं हुआ है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद के समान वस्तु बना हुआ है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था। मूल जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है-

“3. वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए विचाराधीन उत्पाद “एनिलिन” है जिसे “एनिलिन तेल” के रूप में भी जाना जाता है। एनिलिन एक पारदर्शी, तैलीय तरल है और एक प्राथमिक अमाइन सम्मिश्रण है। ताजा आसुत होने पर इसका रंग हल्के पीले रंग के तरल में बदल जाता है। प्रकाश या हवा के संपर्क में आने पर इसका रंग गहरा हो जाता है। एनिलिन एक बुनियादी कार्बनिक रसायन है, जो दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, रंगों और रंग मध्यवर्ती जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए अनिवार्य है।

4. संबद्ध उत्पाद कोड 29214110 के तहत अध्याय शीर्षक 29 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

12. प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों तथा इस जांच में किए गए अनुरोधों की जांच को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के उसी क्षेत्र की पुष्टि करते हैं जो कि पहले अधिसूचित किया गया था। विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित है -

“एनिलिन जिसे एनिलिन तेल के नाम से भी जाना जाता है”।

13. यह उत्पाद सीमा शुल्क कोड 29214110 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है।

14. यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है तथा किसी भी तरह से संबद्ध जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशों, तकनीकी विनिर्देशों, विनिर्माण प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों तथा प्रयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण तथा विपणन, तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित सामानों के तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है तथा विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया था।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

16. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

क. समर्थक आर.के. सिंथेसिस के लिए बिक्री या निष्पादन के आंकड़े आवेदन-पत्र में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

17. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. यह आवेदन-पत्र गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था और आर.के. सिंथेसिस लिमिटेड ने इसका समर्थन किया है। जांच की अवधि के दौरान बाजार में इस उत्पाद का उत्पादन करने वाले कोई अन्य उत्पादक नहीं हैं।

ख. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, एक अन्य घरेलू उद्योग, आर.के. सिंथेसिस लिमिटेड ने एनिलीन के लिए अपना संयंत्र स्थापित किया है।

ग. दीपक केम टेक लिमिटेड (डीसीटीएल) एनिलीन की *** एमटी की क्षमता स्थापित कर रहा है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन-पत्र गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड ने प्रमाणित किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

19. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, एक अन्य घरेलू उत्पादक, आर.के. सिंथेसिस ने क्षति अवधि के दौरान अपना उत्पादन शुरू किया। इस कंपनी ने आवेदन-पत्र का समर्थन किया है। आर.के. सिंथेसिस ने *** एमटी की क्षमता संस्थापित की है। समर्थक ने अपनी संस्थापित क्षमता, उत्पादन, घरेलू तथा निर्यात बिक्री के संबंध में सूचना देते हुए समर्थन पत्र दायर किया है।

20. जांच की अवधि में भारत में एनिलीन का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, यह देखा जाता है कि दीपक केम टेक लिमिटेड (डीसीटीएल) ने गुजरात सरकार के साथ एनिलीन की *** एमटी क्षमता के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। घरेलू उद्योग ने सूचना दी है कि उत्पादन 2027 में शुरू होने की संभावना है।

21. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आवेदन-पत्र के साथ समर्थक के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि समर्थक द्वारा दायर समर्थन पत्र आवेदन-पत्र दायर करने के बाद का था और इसे अन्य हितबद्ध

पक्षकारों के साथ परिचालित किए गए अगोपनीय आवेदन-पत्र का भाग नहीं बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, लिखित अनुरोध में समर्थक के उत्पादन और बिक्री के रुझान प्रदान किए गए थे।

22. नीचे दी गई तालिका आवेदक और समर्थक के उत्पादन को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आवेदक)	एमटी	***	***	***	***
2	आरके सिंथेटिक्स लिमिटेड (अन्य भारतीय उत्पादक)	एमटी	-	***	***	***
3	कुल भारतीय उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
4	आवेदक का हिस्सा	%	100%	90-100%	90-100%	90-100%

23. यह नोट किया जाता है कि आवेदक नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है, भले ही नियम 5(3) के अभिप्राय से आधार नियम 23 के तहत शुरू की गई निर्णायक समीक्षा में सिद्ध किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

ड. विविध अनुरोध

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

24. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए विधिवत प्रमाणित अनुरोध नहीं किया है।
- ख. जबकि आवेदक ने पिछले 30 वर्षों में सीएनए और एनबी के लिए चार बार क्षमता जोड़ी है, आवेदक ने पिछले 30 वर्षों में अर्थात् 1995 से विचारधीन की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाई है।
- ग. आवेदक व्यापार उपाय जांचों का आदतन प्रयोक्ता है और 20 से अधिक वर्षों से व्यापार उपाय संरक्षण का लाभ ले रहा है।
- घ. घरेलू उद्योग ने निर्यातकों द्वारा निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता के बारे में निराधार आरोप लगाए हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए अपेक्षाओं का पालन किया है।
- ख. जबकि आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर सांद्रित नाइट्रिक एसिड और नाइट्रो बेंजीन की क्षमता को जोड़ा गया है, पिछले दो दशकों में विभिन्न स्रोतों से भारत में पाटित आयातों के अत्यधिक आवक के कारण आवेदक के लिए एनिलीन बेचना गैर-अर्थक्षम रहा।
- ग. विभिन्न स्रोतों से पाटित आयातों के कारण आवेदक ने पिछले 20 वर्षों से व्यापार उपचार उपायों का सहारा लिया है।
- घ. एक स्रोत से दूसरे स्रोत पर पाटन के स्थानांतरण ने आवेदक को उचित लाभ के साथ उचित लंबी अवधि के लिए काम करने का मौका नहीं दिया है। आवेदक इन सभी वर्षों के दौरान पाटन के प्रति सुभेद्य रहा है।
- ड. संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों ने अत्यधिक और अनुचित गोपनीयता का दावा किया है, जिसने आवेदक को कोई भी सार्थक टिप्पणी करने से रोका है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 26 जहां तक पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि आवेदक ने विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र नहीं दिया है और व्यापार सूचना 03/2021 का पालन नहीं किया है, प्राधिकारी को इस कथन में कोई आधार नहीं दिखता है तथा उनका मानना है कि आवेदक ने विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा किया है। वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर जांच शुरू की गई थी। आवेदक ने अपने आवेदन-पत्र में चीन जन.गण.में निर्यातकों के साथ क्षमता विस्तार का विवरण तथा तीसरे देश के निर्यात की सूचना उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त, जांच शुरू करने पर सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने आंकड़े तथा विचार प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में संगत सीमा तक प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है।
27. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार उपायों का अभ्यस्त प्रयोक्ता है तथा 20 वर्षों से अधिक समय से पाटनरोधी शुल्क का लाभ ले रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच है। कानून में इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि घरेलू उद्योग कितनी बार विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों की अनुचित व्यापार परिपाटियों से समाधान की मांग कर सकता है और न ही इस बात पर कोई प्रतिबंध है कि कितनी बार पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सकता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिशें प्राधिकारी द्वारा जांच के बाद और अपेक्षित कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर ही की जाती हैं।
28. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक ने कंसन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोबेंजीन जैसे अपस्ट्रीम उत्पादों के लिए क्षमता विस्तार किया है, लेकिन मांग और आपूर्ति में भारी अंतर होने के बावजूद विचाराधीन उत्पाद के लिए नहीं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चूंकि भारतीय बाजार में एनिलीन का पाटन किया जा रहा था, अतः आवेदक के लिए कंसन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को घरेलू बाजार में बेचना अधिक अर्थक्षम था, बजाए इसके कि वह इसका उपभोग करे और एनिलीन का उत्पादन करे। यह देखा जाता है कि वर्तमान जांच में आवेदक को एनिलीन में वित्तीय घाटे हुए हैं। कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार, विगत में उत्पादन बढ़ाने की असमर्थता आवेदक को पाटन से उपाय की मांग करने से अपात्र नहीं बनाती है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी चीन से एनिलीन की मध्यावधि समीक्षा जांच का संदर्भ देते हैं जिसमें निम्नलिखित पाया गया था: -

"39. प्राधिकारी ने यह भी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां किसी व्यापारिक उद्यम के पास बाजार में उत्पाद बेचने या उसकी कैप्टिव खपत करने का विकल्प होता है, और व्यापारिक उद्यम कैप्टिव खपत करने के बजाय बाजार में इनपुट बेचने का फैसला करता है, तो यह निर्णय की सापेक्ष अर्थक्षमता को दर्शाता है। इससे कम से कम यह पता चलता है कि बाजार में ऐसे इनपुट का उत्पादन और बिक्री निचले स्तर के उत्पाद में खपत के बजाए अधिक लाभप्रद हैं।"

29. उपर्युक्त कारणों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी इस अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है कि विगत में क्षमता विस्तार न होने के कारण आवेदक का उपचार मांगने का अधिकार और आधार समाप्त हो गया है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

30. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. धारा 15 के तहत 15 वर्ष की संक्रमण अवधि की समाप्ति स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि "प्रतिनिधि देश" पद्धति अब वैध नहीं है, और सामान्य मूल्य अब चीन की कीमतों और लागतों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ख. फास्टनर्स मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने पुष्टि की है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल का पैराग्राफ 15(घ) पैराग्राफ 15(क) के प्रावधानों को 11 दिसंबर, 2016 के बाद अवैध कर देता है।
- ग. जिलिन रिसुन कोनेल ने मध्यस्थ निर्यातक केम्पार एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भारत में संबद्ध सामान बेचा है। इस प्रकार, व्यक्तिगत दरें प्रदान की जानी चाहिए।
- घ. चीन जन.गण.को बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर दिया जाना चाहिए और सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुसार की जानी चाहिए।
- ड. नियमावली के अनुबंध 1 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक अनुक्रम का प्रावधान है। आवेदक ने पहले दो तरीकों को पूरी तरह से छोड़ दिया है और उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।
- च. यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से काफी आयात होते हैं और सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इन आयातों पर विचार किया जाना चाहिए।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

31. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. प्राधिकारी के अभिगम नयाचार और परिपाटी के अनुसार, चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था उपचार की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब उसका दावा किया जाए और उसकी उपयुक्तता दर्शाई जाए।

- ख. चीनी उत्पादकों ने भाग लिया है, परंतु किसी भी उत्तरदाता चीनी उत्पादक ने वर्तमान जांच में एमईटी दायर नहीं किया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी शुल्क की नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।
- ग. जांच की अवधि में उत्पाद की कीमत में काफी उतार-चढ़ाव आया है। आयात मूल्य और आवेदक की कीमत के बीच भारित औसत के आधार पर कोई भी विश्लेषण उचित नहीं होगा।
- घ. भाग लेने वाले चीनी उत्पादकों ने जांच की अवधि के प्रत्येक महीने में तुलनीय मात्रा में निर्यात नहीं किया है। वानहुआ ग्रुप ने जांच की अवधि (3) महीनों में निर्यात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, (4) महीनों में आयात की मात्रा बहुत कम है।
- ङ. मात्रा और कीमत में उतार-चढ़ाव के साथ, औसत सामान्य मूल्य के साथ तुलना उचित नहीं होगी।
- च. कोनेल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और जिलिन रिसुन कोनेल केमिकल कंपनी लिमिटेड को वर्तमान जांच में अलग से शुल्क नहीं दिया जाना चाहिए। इन उत्पादकों ने जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति नहीं की है।
- छ. अन्य देशों से भारत को निर्यात मूल्य अनुमानित उत्पादन लागत से कम है। इसलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ से निर्यात कीमत को सामान्य मूल्य के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

क. सामान्य मूल्य

32. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश

में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

33. निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर किया गया है:

- क. वानहुआ केमिकल ग्रुप कं., लिमिटेड
- ख. वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्रा. लि.
- ग. वानहुआ केमिकल (यंताई) ट्रेडिंग कं., लिमिटेड
- घ. केम्पार एनर्जी प्रा. लि.
- ङ. जिलिन रिसुन कॉनेल केमिकल कं., लिमिटेड
- च. रिसुन मार्केटिंग लिमिटेड

34. प्राधिकारी चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित संगत प्रावधानों को नोट करते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अंतर्गत प्रावधान नीचे दिए गए अनुसार है:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय उप उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।

8 (1) “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश” वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियों पर पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।”

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू.टी.ओ.के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो

कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, विक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो”

35. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानने की धारणा के साथ कार्यवाही की। जांच की शुरुआत पर, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत की सूचना का जवाब देने और इस बारे में सूचना प्रदान करने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़े/सूचना को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जन. गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।
36. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“ (क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और विक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने

वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि चीन जन.गण. के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में एमईटी स्तर का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंडों की अपेक्षा होती है।
38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित अवधारणाओं का खंडन करने के लिए अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी है।
39. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने की तीन पद्धतियां निर्धारित की गई हैं: (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों

के तहत, सामान्य मूल्य का निर्धारण सबसे पहले किसी प्रतिनिधिक देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।

40. आवेदन-पत्र दाखिल करने के स्तर पर, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि चीन जन.गण.के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत समायोजित किया जाना चाहिए।
41. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोपीय संघ से निर्यात कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। प्राधिकारी मानते हैं कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में एक अनुक्रम का प्रावधान है जिसका पालन किया जाना आवश्यक है। यह देखा गया है कि गैर-संबद्ध देशों से काफी आयात हुए हैं। जबकि चीन जन.गण. से आयात मात्रा 52,869 एमटी हैं, अगली सबसे अधिक आयात मात्रा 49,197 एमटी यूरोपीय संघ से है। यूरोपीय संघ एक गैर-संबद्ध देश है, जिसमें कोई पाटनरोधी उपाय लागू नहीं है और आयात मात्रा काफी हैं, यूरोपीय संघ से सीआईएफ कीमत प्रकृति में प्रतिनिधिकारक हैं। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ से निर्यात भारतीय बाजार के लिए हैं और तुलनीय समय अवधि में हो रहे हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश माना है और नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। चूंकि यह कीमतें सीआईएफ स्तर पर हैं, अतः विभिन्न कारकों, यथा समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा और अन्य खर्चों के संबंध में उपयुक्त समायोजन कारखानागत कीमत निकालने के लिए सतत परिपाटी के अनुसार किए गए हैं। इस प्रकार परिकलित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित हैं।

क. निर्यात कीमत

मेसर्स वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (उत्पादक), मेसर्स वानहुआ केमिकल (यंताई) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर (व्यापारी), मेसर्स वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (व्यापारी), और मेसर्स केम्पार एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (व्यापारी) द्वारा भारत को निर्यात

i. वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड

42. वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. के कंपनी कानून के तहत निगमित और पंजीकृत लिमिटेड कंपनी है। यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि की अवधि के दौरान, वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. ने दो संबंधित निर्यातकों/व्यापारियों अर्थात् वानहुआ केमिकल (यंताई) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, (***) एमटी) और वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड (***) एमटी) के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को आरएमबी *** के बीजक मूल्य के संबद्ध सामानों का *** एमटी बेचा है। यह भी नोट किया जाता है कि वानहुआ केमिकल (यंताई) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ने वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को उन्हीं संबद्ध सामानों की पुनः बिक्री की है।
43. यह भी नोट किया जाता है कि उत्पादक द्वारा वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड को बेचे गए कुल संबद्ध सामानों में से निर्यातक/व्यापारी ने भारत को सीधे ही (***) मीट्रिक टन) संबद्ध सामानों बेचे हैं और शेष को केम्पार एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर नामक अन्य असंबंधित निर्यातक/व्यापारी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को

बेचा गया है। उत्पादक/निर्यातक ने कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, पत्तन तथा अन्य संबद्ध व्ययों और अंतर्देशीय परिवहन के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। निर्यातक/उत्पादक द्वारा दावा किए गए समायोजन को डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है, तथा इस प्रकार निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दी गई है:

ii. जिलिन रिसुन कॉनेल केमिकल कंपनी लिमिटेड

44. यह दावा किया गया है कि जिलिन रिसुन कॉनेल केमिकल कंपनी लिमिटेड (जिलिन रिसुन) "पीआरसी कॉर्पोरेट कानून" के अनुसार स्थापित लिमिटेड देयता कंपनी है (आंशिक रूप से चीनी हांगकांग, चीनी मकाऊ और चीनी ताइपे से निवेश से पूंजी निवेशित) है।

45. यह दावा किया गया है कि जांच अवधि के दौरान, मेसर्स जिलिन रिसुन कॉनेल केमिकल कंपनी लिमिटेड ने रिसुन मार्केटिंग लिमिटेड नामक एक संबंधित निर्यातक/व्यापारी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को आरएमबी *** के बीजक मूल्य वाले (***) एमटी संबद्ध) संबद्ध सामानों का केवल एक लेनदेन किया है। रिसुन मार्केटिंग लिमिटेड ने आगे बताया है कि उसके ग्राहक केम्पर एनर्जी लिमिटेड ने अप्रैल 2024 (जांच की अवधि के बाद की अवधि) में भारत को शिपमेंट के पुनर्विक्रय के लिए वाणिज्यिक बीजक जारी किए हैं। अतः, केम्पर एनर्जी लिमिटेड द्वारा शिपमेंट की रिपोर्ट नहीं दी गई थी। तथापि, चूंकि केम्पार एनर्जी लिमिटेड द्वारा रिसुन मार्केटिंग लिमिटेड, चीन जन.गण. से भारत में खरीदे गए संबद्ध सामानों की बिक्री के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, और भारत को निर्यात बिक्री की श्रृंखला अपूर्ण है, अतः जिलिन रिसुन कॉनेल केमिकल कंपनी लिमिटेड को अलग मार्जिन प्रदान नहीं किया गया है।

iii. चीन जन. गण. के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत।

46. चीन के अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है, तथा इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

47. उपर्युक्त सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के निर्धारण के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है, जिसे नीचे दर्शाया गया है।

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य (यूएसडॉ./ एमटी)	निवल निर्यात कीमत (यूएसडॉ./ एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडॉ./एमटी)	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
1	वानहुआ गुप	***	***	***	***	10-20%
2	कोई अन्य	***	***	***	***	25-25%

छ. क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संपर्क

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

48. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग उस स्तर तक गिर गया जो भारतीय मांग को पूरा करने के लिए अत्यधिक अपर्याप्त था।
- ख. आवेदक आर्थिक मापदंडों के संबंध में आयातों के प्रभाव पर साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा है।
- ग. वित्तीय वर्ष 2020-2021 और जांच की अवधि में कीमत कटौती नकारात्मक है। इस प्रकार, आयातों का आवेदक की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
- घ. मांग-आपूर्ति के अंतर ने आवेदक को आयात की तुलना में अधिक कीमतों पर संबद्ध सामानों को बेचने में सक्षम बनाया है। प्रयोक्ता उच्च कीमतों पर खरीदन करने के लिए मजबूर हैं।
- ङ. चीन जन.गण. से आयात का कोई कीमत प्रभाव नहीं है और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात कीमत चीन जन.गण. से आयात कीमत से कम है।
- च. कोई मूल्य ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं है क्योंकि आवेदक और निर्यातक फार्मूला-आधारित कीमत निर्धारण के आधार पर संविदा के तहत सामान बेचते हैं।
- छ. आवेदक की मूल्यह्रास लागत संबद्ध सामानों की क्षमता में किसी भी वृद्धि के बिना जांच की अवधि में नाटकीय स्तर तक बढ़ गई है।
- ज. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क का संरक्षण होने के बावजूद अपने उत्पादन और बिक्री को कम कर दिया है और अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
- झ. यह विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या अन्य देशों से आयात में वृद्धि से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- ञ. चीन जन.गण. से आयात में 8% की वृद्धि हुई है जबकि बाजार में समग्र मांग में 65% की वृद्धि हुई है।
- ट. घरेलू बिक्री में कमी चीन जन.गण. से आयातों को छोड़कर अन्य कारकों से है।
- ठ. प्राधिकारी द्वारा 22% पर नियोजित पूंजी पर आय की अनुमति देना बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और कानून के अनुसार नहीं है।
- ड. घरेलू उद्योग आंतरिक मुद्दों, वैश्विक बाजार की स्थितियों, कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, कोविड-19 और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे महत्वपूर्ण कारकों को हल करने में विफल रहा है, जिसने घरेलू उद्योग को प्रभावित किया है।
- ढ. वानहुआ निर्धारित रखरखाव के कारण कम क्षमता पर काम कर रहा था और इसका संयंत्र पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था।

छ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

49. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. संबद्ध देश से आयात निरपेक्ष रूप से तथा भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में लगातार बढ़ा है।
- ख. संबद्ध देश से आयात केवल वर्ष 2023-2024 को छोड़कर निरंतर बढ़ा है।

- ग. जांच की अवधि में आयात में गिरावट कुछ समय के लिए वानहुआ समूह के संयंत्र के बंद होने के कारण हुई। इसके परिणामस्वरूप भारत में अन्य देशों से आयात में भी वृद्धि हुई है।
- घ. जांच अवधि के बाद संबद्ध देश से आयात में तेजी से वृद्धि हुई है।
- ङ. सभी स्रोतों से संचयी आयात में, कुल आयात में चीन से आयात का हिस्सा सबसे अधिक है।
- च. आवेदक को घरेलू बाजार में बेचने के लिए आयात कीमत से कम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- छ. बिक्री कीमत में वृद्धि की दर बिक्री की लागत में वृद्धि की दर से काफी कम होने के कारण महत्वपूर्ण कीमत न्यूनीकरण है।
- ज. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद, आवेदक का हिस्सा उसकी क्षमता से काफी कम रहा है।
- झ. आवेदक का उत्पादन 2021-2022 में बढ़ा, उसके बाद 2022-2023 में काफी गिरावट आई, जब संबद्ध देश से आयात सबसे अधिक था। जांच की अवधि में उत्पादन आधार वर्ष और 2021-2022 से कम था।
- ञ. विचाराधीन उत्पाद के मासिक कीमत में काफी उतार-चढ़ाव हैं, जिसके कारण आयात कीमत और आवेदक की कीमत के बीच भारित औसत के आधार पर कोई भी विश्लेषण उचित नहीं होगा। मासिक कीमत कटौती, मासिक पाटन मार्जिन और मासिक क्षति मार्जिन के निर्धारण की आवश्यकता है।
- ट. जांच की अवधि में उच्चतम मासिक और निम्नतम मासिक आयात कीमत के बीच का अंतर चीन के लिए **%, आवेदक के लिए **%, यूएसए के मामले में **%, नीदरलैंड के मामले में **% और बेल्जियम के मामले में **% था।
- ठ. प्रत्येक वर्ष मांग में लगातार वृद्धि के बावजूद, आवेदक की घरेलू बिक्री में सुधार नहीं हुआ। जांच की अवधि के दौरान आवेदक की बिक्री में केवल इसलिए सुधार हुआ क्योंकि उसने घाटे में बिक्री की। आवेदक की बिक्री उस स्तर पर है जो उसकी क्षमता और बाजार में मांग से काफी कम है।
- ड. आवेदक की बिक्री उस स्तर पर है जो उसकी क्षमता और बाजार की मांग से काफी नीचे है।
- ढ. संबद्ध देश से आयातों का बाजार हिस्सा वित्तीय वर्ष 2022-2023 तक काफी अधिक रहा और जांच की अवधि में घट गया।
- ण. आवेदक के पास मांग में बाजार हिस्सेदारी का केवल **% हिस्सा है। जबकि, यदि इष्टतम क्षमता पर प्रचालन किया जाता, तो आवेदक का बाजार हिस्सा **% हो सकता था।
- त. आवेदक को जांच की अवधि में हानियां हुई हैं। आवेदक का व्याज पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर आय जांच की अवधि में नकारात्मक हो गया है।
- थ. क्षति रहित कीमत के लिए नियोजित पूंजी पर आय के निर्धारण के लिए, प्राधिकारी को 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नियोजित पूंजी पर औसत आय पर विचार करना चाहिए। यह

वह अवधि थी जब घरेलू बाजार में उत्पाद का कोई पाटन नहीं हुआ था और आवेदक पर्याप्त लाभकारी कीमतों पर उत्पाद बेचने में सक्षम था।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

50. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।
51. प्राधिकारी घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति तथा कारणात्मक संबंध से संबंधित किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट करते हैं और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण करते हैं। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को स्वतः संबोधित किया गया है।
52. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच किए जाने से पूर्व घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है।
53. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों की भी जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को संबोधित किया गया है।
54. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि दावा की गई क्षति अन्य देशों से किए गए आयातों के कारण से है, प्राधिकारी ने अन्य देशों से किए गए आयातों की मात्रा और कीमतों की जांच की है। यह देखने में आया है कि जांच की अवधि के दौरान चीन, यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से काफी मात्रा में आयात हुए हैं। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों की कीमतें चीन से आयातों की कीमतों के समान स्तर पर हैं। यह भी देखने में आया है कि चीन से आयातों में घरेलू बाजार का सबसे अधिक अंश शामिल है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह भी देखने में आया है कि चीन में संयंत्र बंद होने/ रखरखाव के चलते जांच की अवधि में चीन से आयातों में गिरावट आई है। प्राधिकारी ने एनिलीन के संबंध में जांच की अवधि के बाद के आयात के आंकड़ों की भी जांच की है और यह नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों की मात्रा में काफी कमी आई है, जबकि इसी अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों में काफी वृद्धि हुई है।

55. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध यह किया कि वे उस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित प्रतिफल पर विचार करें, जिस अवधि में कोई पाटन नहीं हुआ था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के तहत संगत दिशानिर्देश अच्छी तरह से निर्धारित किए गए हैं। प्राधिकारी ने निरंतर रूप से, नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल अनुमत किया है और चूंकि उन्हें अपनी स्थापित प्रथा से विचलित होने का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता, अतः वर्तमान जांच में भी इसी को अपनाया गया है।

छ.3.1. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/ खपत का आकलन

56. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग, समर्थक और सभी स्रोतों से एनिलीन के आयातों की घरेलू बिक्री के योग के रूप में किया है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	पवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	65	91
2	समर्थक की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	***	***	***	***
3	संबद्ध देश के आयात	मी. टन	47,900	65,135	76,705	52,869
4	अन्य देशों के आयात	मी. टन	23,718	24,203	17,331	94,867
5	कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***
	पवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	111	172

57. यह देखने में आया है कि आधार वर्ष 2020-2021 की तुलना में, विचाराधीन उत्पाद की मांग में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई है, 2022-23 में कमी आई है और जांच की अवधि में पुनः महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

ख. निरपेक्ष और सापेक्ष आयात

58. क्षति अवधि और जांच की अवधि में निरपेक्ष और सापेक्ष आयातों की मात्रा के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	संबद्ध आयात	मी. टन	47,900	65,135	76,705	52,869
2	अन्य आयात	मी. टन	23,718	24,203	17,331	94,867
3	कुल आयात	मी. टन	71,618	89338	94036	147736
4	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देश के आयात					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	225	112
ख	कुल मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	144	64
ग	कुल आयात	%	***	***	***	***

59. यह देखने में आया है कि:

क. आधार वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-2022 में संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है, वर्ष 2022-2023 में इसमें और वृद्धि हुई है तथा जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। यह विगत वर्षों में आयातों की मात्रा में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

ख. संबद्ध देश से आयातों में वर्ष 2022-23 तक भारतीय उत्पादन के संबंध में वृद्धि हुई है, लेकिन जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। खपत और कुल आयातों के संबंध में, आयातों के लिए भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखने में आई है।

ग. संबद्ध देश से आयात वर्ष 2022-2023 तक भारतीय उत्पादन, भारतीय मांग और कुल आयातों के संबंध में काफी अधिक रहे।

छ.3.2. पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

60. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में महत्वपूर्ण कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम करना अथवा कीमत में वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक होती।

क. कीमत कटौती

61. कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है। नीचे दी गई तालिका में क्षति अवधि के दौरान औसत आधार पर संबद्ध देश से हुई कीमत कटौती को दर्शाया गया है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	बिक्री कीमत	₹/ मी. टन	***	***	***	***
2	पहुंच कीमत	₹/ मी. टन	***	***	***	***
3	कीमत कटौती	₹/ मी. टन	***	***	***	***
4	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
5	संबद्ध देश	रेंज	30-40%	0-10%	0-10%	0-10%

62. यह देखने में आया है कि क्षति अवधि के दौरान कीमत कटौती में उतार-चढ़ाव आया है। क्षति अवधि के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक है।

63. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उत्पाद की कीमत में काफी उतार-चढ़ाव आया है और मासिक आधार पर कीमत कटौती का निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है। नीचे दी गई तालिका में जांच की अवधि के दौरान मासिक आधार पर कीमत कटौती को दर्शाया गया है।

64. जांच की अवधि के दौरान मासिक आधार पर कीमत कटौती का विश्लेषण

क्र. सं.	माह	मी. टन में आयात	निवल बिक्री कीमत ₹./ मी. टन	पहुंच कीमत ₹./ मी. टन	कीमत कटौती ₹./ मी. टन	कीमत कटौती %	रेंज (%)
1	अप्रैल - 23	10,388	***	***	***	***	20-30
2	मई - 23	3,170	***	***	***	***	0-10
3	जून - 23	2,895	***	***	***	***	0-10
4	जुलाई - 23	662	***	***	***	***	नकारात्मक
5	अगस्त - 23	2,385	***	***	***	***	नकारात्मक
6	सितंबर - 23	5,807	***	***	***	***	0-10
7	अक्टुबर - 23	47	***	***	***	***	नकारात्मक
8	नवंबर - 23	69	***	***	***	***	नकारात्मक
9	दिसंबर - 23	1,962	***	***	***	***	नकारात्मक
10	जनवरी - 24	5,345	***	***	***	***	नकारात्मक
11	फरवरी - 24	12,041	***	***	***	***	10-20
12	मार्च - 24	8,099	***	***	***	***	0-10
13	भारित औसत	52,869	***	***	***	***	0-10

ख. कीमत कमी / गिरावट

65. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित किए गए आयातों से घरेलू कीमतों में गिरावट आ रही हैं और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम करना है अथवा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य रूप से हो गई होती, अतः क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	बिक्रियों की लागत	₹/ मी. टन	***	***	***	***
	परिवर्तन	₹/ मी. टन	-	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	181	227	194
2	निवल बिक्री कीमत	₹/ मी. टन	***	***	***	***
	परिवर्तन	₹/ मी. टन	-	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	161	167	140

66. यह देखने में आया है कि वर्ष 2021-2022 में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, बिक्री की कीमत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में बिक्री की लागत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की और वृद्धि हुई है, लेकिन बिक्री की कीमत में केवल [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। बिक्री की कीमत में वृद्धि की दर आवेदक की लागत बिक्री में हुई वृद्धि की कम दर पर है।
67. वर्ष 2023-24 (जांच की अवधि) में, जांच की अवधि में बिक्री की लागत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई है, बिक्री की कीमत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई है। क्षति अवधि में, बिक्री की कीमत में हुई वृद्धि की दर बिक्री की लागत में वृद्धि से कम है। अतः आयातों के कारण क्षति अवधि में बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आई है।

छ.3.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव

68. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के तहत यह अपेक्षित है कि क्षति का निर्धारण करने में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित किए गए आयातों के परिणामी प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी। घरेलू उत्पादकों पर ऐसे उत्पादों के पाटित किए गए आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में यह भी प्रावधान किया गया है कि घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का एक उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, वस्तुसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और

संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों के संबंध में नीचे चर्चा की गई है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

69. क्षति अवधि में क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री के संबंध में सूचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	स्थापित क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	66	90
3	उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	66	90
4	घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	65	91

70. यह देखने में आया है कि:-

- क. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता समान रही है।
- ख. आवेदक के क्षमता उपयोग में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई, वर्ष 2022-23 में कमी आई, लेकिन जांच की अवधि में पुनः वृद्धि हो गई। क्षमता उपयोग कम रहा है।
- ग. आवेदक के उत्पादन में वर्ष 2021-2022 में वृद्धि हुई, वर्ष 2022-2023 में कमी आई, लेकिन जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हो गई। क्षति अवधि के दौरान देखा जाए, तो घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है।
- घ. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वर्ष 2021-2022 में वृद्धि हुई, वर्ष 2022-23 में कमी आई और जांच की अवधि में वृद्धि हो गई। क्षति अवधि में घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।
- ड. घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्री आवेदक की मौजूदा क्षमता से काफी कम रही है।

ख. बाजार अंश

71. इस अवधि में आयात और घरेलू उद्योग के बाजार अंश के संबंध में सूचना इस प्रकार थी :

क्र. सं.	बाजार अंश	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	58	53
2	समर्थक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	100	224	245
3	भारतीय उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	62	58
3	संबद्ध देश के आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	143	64
4	अन्य देशों के आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	66	233

72. यह देखने में आया है कि: -

- क. घरेलू उद्योग के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- ख. भारतीय उद्योग के बाजार अंश में भी गिरावट आई है।
- ग. संबद्ध देश से आयातों के बाजार अंश में वर्ष 2022-2023 तक लगातार वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई है।
- घ. असंबद्ध देशों से आयातों के बाजार अंश में वर्ष 2022-2023 तक कमी आई है और जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई है।

ग. लाभप्रदता, नकदी लाभ और निवेशों पर प्रतिफल

73. लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकदी लाभ के संबंध में सूचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	लाभ/ (हानि)	₹/ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	8	-2
2	पीबीआईटी	₹/ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	8	-1
3	नकदी लाभ	₹/ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	10	2
4	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	7	-1

74. यह देखने में आया है कि घरेलू उद्योग के लाभ में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है और जांच की अवधि में यह हानि में परिवर्तित हो गया है।
75. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2022-2023 तक कर पूर्व लाभ, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर सकारात्मक प्रतिफल अर्जित किया है। ब्याज पूर्व लाभ, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतफल में वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में काफी कमी हो गई है और जांच की अवधि के दौरान यह नकारात्मक हो गया है।

घ. वस्तुसूची

76. वस्तुसूची के संबंध में सूचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	प्रारंभिक वस्तुसूची	मी. टन	***	***	***	***
2	अंतिम वस्तुसूची	मी. टन	***	***	***	***
3	औसत वस्तुसूची	मी. टन	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	91	90

77. यह देखने में आया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत वस्तुसूची में गिरावट आई है।

ङ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

78. क्षति अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में सूचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	81	89
2	वेतन एवं मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	166	188
3	उत्पादकता प्रति दिन	मी. टन / दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	66	90
4	उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी. टन / संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	81	101

79. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उत्पादन के अनुरूप वृद्धि हुई है। भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है, जबकि कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है।

च. विकास

80. विकास के संबंध में सचना नीचे दी गई है: -

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	क्षमता	वर्ष / वर्ष	-	-	-
2	उत्पादन	वर्ष / वर्ष	18%	-44%	37%
3	बिक्रियां	वर्ष / वर्ष	17%	-45%	40%
4	बाजार अंश	वर्ष / वर्ष	-4%	-41%	-2%
5	लाभ / हानि	वर्ष / वर्ष	8%	-92%	-124%
6	नकदी लाभ	वर्ष / वर्ष	8%	-91%	-78%
7	आरओसीई	वर्ष / वर्ष	-11%	-92%	-117%

81. यह देखने में आया है कि आवेदक ने कीमत संबंधी मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

82. यह देखने में आया है कि देश में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग घाटे में चल रहा था। अतः उनकी पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ज. पाटन का मार्जिन

83. यह देखने में आया है कि चीन जन. गण. से भारत में संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा है और पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और महत्वपूर्ण है।

ज. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

84. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को अन्य के साथ-साथ, पाटित किए गए आयातों के अलावा किसी भी ज्ञात कारक की जांच करनी अपेक्षित होती है जिनसे कि घरेलू उद्योग को हानि हो रही हैं अथवा हानि होने की संभावना है ताकि पाटित किए गए आयातों के लिए इन अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति को जिम्मेदार न ठहराया जा सके। जबकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संबंध की जांच पहले ही की जा चुकी है, प्राधिकारी ने जांच की कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों के कारण घरेलू उद्योग को हानि हुई है अथवा हानि होने की संभावना है। यह जांच की गई कि क्या नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान हो सकता है अथवा योगदान होने की संभावना है।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

85. यह देखने में आया है कि यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य स्रोतों से न्यूनतम सीमा से अधिक आयात हुए थे। प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन जन. गण. से मासिक आयात कीमत की तुलना की है और यह पाया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ से आयात कीमत जांच की अवधि के दौरान चीन से आयात कीमत के समान स्तर पर है।

ख. मांग में कमी और/ अथवा उपभोग की पद्धति में परिवर्तन

86. क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, भविष्य में मांग में और वृद्धि होने की संभावना है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

87. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोई भी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

88. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

ङ. निर्यात निष्पादन

89. घरेलू उद्योग ने उत्पाद का निर्यात नहीं किया है अतः निर्यात निष्पादन क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

च. अन्य उत्पादों का निष्पादन

90. प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन के संबंध में आंकड़ों पर विचार किया है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्री किए गए अन्य उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग को क्षति होने का संभावित कारण नहीं है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

91. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध III के साथ पठित यथासंशोधित नियमावली में निर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/ आंकड़ों को अपनाकर क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत के साथ क्षतिरहित कीमत की तुलना की गई है। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए कच्ची सामग्रियों और यूटिलिटी के श्रेष्ठ उपयोग तथा उत्पादन क्षमता के श्रेष्ठ उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय और/ अथवा परिसंपत्तियों को उत्पादन लागत और/ अथवा क्षतिरहित कीमत से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल संपत्तियां एवं औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) को व्याज, कॉर्पोरेट कर तथा लाभ की वसूली के लिए अनुमति दी गई है ताकि नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित क्षतिरहित कीमत निकाली जा सके।

क्र. सं.	विवरण	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन		
		\$/ मी. टन	\$/ मी. टन	\$/ मी. टन	%	रेंज
1	वानहुआ समूह	***	***	***	***	0-10%
2	कोई अन्य	***	***	***	***	10-20%

ज. क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

92. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक ने यह कहा है कि वानहुआ केमिकल्स ने यह प्रकट किए बिना एनिलीन की क्षमता का विस्तार किया है कि कंपनी ने डाउनस्ट्रीम मिथाइलेनडाइफिनाइल डायसोसाइनेट (एमडीआई) की क्षमता का भी विस्तार किया है, जहां एनिलीन का कैप्टिव उपयोग किया जा रहा है।
- ख. निर्णायक समीक्षा में, समग्र जांच का फोकस क्षति की संभावना पर है, न कि पाटन और क्षति के वर्तमान स्तर पर।
- ग. आवेदक ने पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना का दावा करने के लिए पाटन अथवा उसे हो रही क्षति के जारी रहने को दर्शाने के लिए जांच की अवधि के बाद का डेटा प्रदान नहीं किया है।
- घ. चीन जन. गण. से आयातों में वर्ष 2020-2021 से जांच की अवधि तक मामूली रूप से वृद्धि हुई है और इसलिए, देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है।
- ङ. आवेदक ने चीन के निर्यातकों के पास सरप्लस क्षमता की उपलब्धता के संबंध में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है।
- च. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत कड़ाई के अनुसार पाटन और क्षति की संभावना का आकलन किया जाना चाहिए।
- छ. यह दावा सही नहीं है कि वानहुआ ग्रुप ने 2022 में विस्तार किया। वास्तव में, किया गया विस्तार महत्वपूर्ण नहीं है। अधिकांश उत्पादन एमडीआई के उत्पादन में आंतरिक रूप से खपत करने के उद्देश्य से है।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

93. घरेलू उद्योग ने संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. प्रभावी उपायों के बावजूद, आयात संबद्ध देश पाटित कीमतों पर आ रहे हैं।
- ख. लागू उपायों के बावजूद संबद्ध देश से आयातों में निरंतर वृद्धि हो रही है।
- ग. देश में सरप्लस मांग होने के बावजूद चीन में उत्पादकों ने अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है। उपायों की समाप्ति के साथ, आयातों में और वृद्धि होने की संभावना है।
- घ. वानहुआ ग्रुप द्वारा की गई क्षमता वृद्धि *** टन के वार्षिक उत्पादन की है। यह वृद्धि अपने आप में वर्तमान भारतीय क्षमता से *** % अधिक है।

- इ. वानहुआ ग्रुप का उत्तर स्वयं ही इस तथ्य की पुष्टि करता है कि किए गए क्षमता विस्तार का उद्देश्य बिक्री और विशेष रूप से भारत को निर्यात बिक्री में वृद्धि करना है। यह देखा जा सकता है कि उत्पादक ने क्षमता का विस्तार किया है और इसके शिपमेंट में तेजी से वृद्धि हुई है।
- च. वानहुआ केमिकल ग्रुप ने 2022 में *** टन एनिलीन के वार्षिक उत्पादन के साथ अपनी क्षमता में काफी विस्तार किया है।
- छ. चीन के निर्यातक तीसरे देशों में पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात कर रहे हैं।
- ज. जिलिन रिसुन कॉनेल केमिकल कंपनी लिमिटेड ने भी मूल जांच में पाटनरोधी उपायों के लागू होने के बाद क्षमता स्थापित की है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

94. वर्तमान जांच चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए गए शुल्कों की एक निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा शुल्क की समाप्ति होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
95. प्राधिकारी ने धारा 9 क (5), नियम 23 और नियमावली के अनुबंध II (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति की आशंका से संबंधित मापदंडों और हितवद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की है।
96. इस तरह की संभावना का विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यविधि उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों का प्रावधान है जिन पर विचार किया जाना अपेक्षित है, अर्थात्
- क. भारत में पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर, जो आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।
- ख. किन्हीं भी अतिरिक्त निर्यातों को समाहित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए। निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त रूप से आसान निपटान योग्य अथवा एक आने वाली, पर्याप्त वृद्धि, जो भारतीय बाजारों में पाटित किए गए निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है,
- ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट अथवा कमी का प्रभाव पड़ेगा और आगे के आयातों की मांग में वृद्धि होगी; और
- घ. वस्तुओं की वस्तुसूची की जांच की जा रही है।
97. प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करने के लिए उपर्युक्त अपेक्षाओं और निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है और यदि ऐसा है, तो क्या इससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सभी संगत सूचनाओं की जांच की है।
- क. भारत में पाटित किए गए आयातों की वृद्धि दर जो आयातों में वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।
98. नीचे दी गई तालिका में संबद्ध देश से आयातों के संबंध में सूचना को दर्शाया गया है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	संबद्ध देश के आयात	मी. टन	47,900	65,135	76,705	52,869
2	कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***

99. यह देखने में आया है कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में आयातों में गिरावट आई है। वानहुआ ग्रुप ने यह भी अनुरोध किया है कि जांच की अवधि में उसके संयंत्र में कुछ समय के लिए उत्पादन को रोक दिया गया था। जांच की अवधि से ठीक पहले के तीन वर्षों में, वानहुआ ग्रुप का निर्यात भारत में कुल आयातों का [***] % था। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के अनुरोध को नोट करते हैं कि जांच की अवधि के बाद आयातों में पुनः वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयातों का सभी स्रोतों से कुल आयातों में सबसे अधिक हिस्सा है।

100. प्राधिकारी ने आयात के संबंध में जांच अवधि के बाद के आंकड़ों की भी जांच की है। यह देखा गया है कि जांच अवधि के बाद चीन जन.गण. से आयात की मात्रा में तीव्र वृद्धि देखी गई है। जबकि चीन से आयात में वृद्धि हुई है, अन्य देशों से आयात में कमी आई है। जब उपाय लागू हैं, तो चीन से आयात में वृद्धि से पता चलता है कि यदि शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है, तो इसमें और वृद्धि की संभावना है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	जांच की अवधि	अप्रैल से दिसंबर 24 (A)	परिवर्तन
1	चीन से आयात	मी. टन	52,869	92,604	39,735
2	यूरोपीय संघ से आयात	मी. टन	49,197	68,608	19,411
3	संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात	मी. टन	45,334	8,794	-36,540
4	अन्य देशों से कुल आयात	मी. टन	94,867	82,156	-12,711

स्रोत – डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के बाद के आंकड़े।

101. नीचे दी गई तालिका जांच के पश्चात की अवधि में चीन और अन्य देशों से आयात मूल्य के बारे में जानकारी दर्शाती है। यह देखा गया है कि चीन पीआर के साथ-साथ अन्य देशों से आयात मूल्य में वृद्धि हुई है, लेकिन चीन पीआर से आयात मूल्य में वृद्धि अन्य देशों से आयात मूल्य की तुलना में काफी कम है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	जांच की अवधि	अप्रैल से दिसंबर 24 (A)	परिवर्तन
1	चीन से आयात	₹/ मी. टन	1,20,874	1,33,734	12860
2	यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से आयात	₹/ मी. टन	1,23,271	1,42,263	18992
3	अंतर	₹/ मी. टन	2,397	8529	6132

स्रोत – डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के बाद के आंकड़े।

ख. स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य क्षमता, जो भारतीय बाजारों में पाटित किए गए निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।

102. नीचे दी गई तालिका में चीन जन. गण. से भाग लेने वाले उत्पादकों की क्षमता और घरेलू बिक्री के संबंध में सूचना को दर्शाया गया दर्शाती है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	वानहुआ ग्रुप	जिलिन रिसुन
1	क्षमता	मी. टन	***	***
2	घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***
3	क्षमता के % के रूप में घरेलू बिक्रियां	%	***	***
4	क्षमता के % के रूप में घरेलू बिक्रियां	रेंज	30-40%	20-30%

103. यह देखने में आया है कि दोनों भागीदार उत्पादकों की क्षमता उनकी घरेलू बिक्रियों से काफी अधिक है। वानहुआ ग्रुप के मामले में घरेलू बिक्री चीन जन. गण. में क्षमता की केवल *** % है। यह दर्शाता है कि उत्पादक सरप्लस क्षमताओं के साथ काम कर रहे हैं।

ग. क्षमता विस्तार

104. घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त सूचना प्रदान की है कि वानहुआ ग्रुप ने क्षमता का विस्तार किया है और *** टन की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि क्षमता वृद्धि एमडीआई, एक डाउनस्ट्रीम उत्पाद के उत्पादन के लिए है। प्राधिकारी ने भागीदार उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया को नोट किया है।

105. यह देखने में आया है कि वानहुआ ग्रुप ने वर्ष 2021-22 में *** मीट्रिक टन की क्षमता वृद्धि होने की सूचना दी है। एक अन्य उत्पादक और निर्यातक के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि मेसर्स जिलिन रिसुन ने वर्ष 2022-23 से उत्पाद का उत्पादन शुरू कर दिया है, और जांच की अवधि के दौरान [*** %] से अधिक अप्रयुक्त क्षमता है।

106. अतः यह माना जाता है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है।

घ. तीसरे देश का पाटन

107. यह देखने में आया है कि वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने तीसरे देश के निर्यातों की सूचना केवल अपने संबंधित पक्षकार, वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्रा. लि. को दी है। वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्रा. लि. ने अपने तीसरे देश के निर्यात के संबंध में सूचना नहीं दी है। अतः सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने ट्रेडमैप डेटा पर भरोसा किया है।

108. तीसरे देश के पाटन के संबंध में सूचना नीचे दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	मात्रा
1	कुल निर्यात	मी. टन	***
2	सामान्य मूल्य से कम निर्यात	मी. टन	***
3	सामान्य मूल्य से कम निर्यात	%	42%

109. यह देखने में आया है कि 42% निर्यात सामान्य मूल्य से कम हैं।

ड. तीसरे देश की क्षतिकारी कीमत

110. यह देखने में आया है कि वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने तीसरे देश के निर्यातों की सूचना केवल अपने संबंधित पक्षकार, वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड को दी है। वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड ने अपने तीसरे देश के निर्यातों के संबंध में सूचना नहीं दी है। अतः सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने ट्रेडमैप डेटा पर भरोसा किया है।

111. क्षतिकारी कीमत पर तीसरे देश के निर्यातों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	मात्रा
1	कुल निर्यात	मी. टन	***
2	एनआईपी से कम निर्यात	मी. टन	***
3	एनआईपी से कम निर्यात	%	18%

112. यह देखने में आया है कि 18% निर्यात एनआईपी से कम हैं।

च. तीसरे देश की कीमतों का आकर्षण

113. यह देखने में आया है कि वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने तीसरे देश के निर्यातों की सूचना केवल अपने संबंधित पक्षकार, वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्रा.लि. को दी है। वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्रा.लि. ने अपने तीसरे देश के निर्यातों के संबंध में सूचना नहीं दी है। अतः सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने ट्रेडमैप डेटा पर भरोसा किया है।

114. कीमत के आकर्षण के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	मात्रा
1	कुल निर्यात	मी. टन	***
2	भारतीय कीमतों से कम निर्यात	मी. टन	***
3	भारतीय कीमतों से कम निर्यात	%	40%

115. यह देखने में आया है कि तीसरे देशों को किए जाने वाले 40% निर्यातों की कीमत भारत को किए जाने वाले निर्यातों की कीमतों से कम है। अतः यह देखने में आया है कि यदि पाटनरोधी उपायों को वापस ले लिया जाता है, तो भारत की ओर निर्यातों के आने की संभावना है।

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामले

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

116. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. भारत में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है, जिसके कारण उपयोगकर्ता आयात करने के लिए बाध्य हैं।
- ख. 10% शुल्क लगाने से समग्र लाभप्रदता में 2% की कमी आएगी।
- ग. डीसीटीएल 2027 में उत्पादन शुरू करेगा, अर्थात् अगले 2 वर्षों तक डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं को मांग और आपूर्ति के बीच अंतर होने के कारण आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ेगा।
- घ. संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क ने प्रयोक्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। आवेदक को पहले ही पाटनरोधी शुल्क के अतिरिक्त, आयातों पर 7.5% सीमा शुल्क का लाभ मिल चुका है, जो घरेलू उद्योग को सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर प्रदान करता है।
- ङ. यदि शुल्कों को जारी रखा जाता है, तो यह कार्य "आत्मनिर्भर भारत" पहल के लक्ष्यों के खिलाफ होगा, जिसका कि उद्देश्य ही आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और एमएसएमई के विकास में सहायता करना है।
- च. डाउनस्ट्रीम उत्पादकों की बढ़ती इनपुट लागत से इसके विकास में कमी आती है।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

117. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, एक अन्य उत्पादक, आर.के. सिंथेसिस ने भारत में एक संयंत्र स्थापित किया है। दीपक केम टेक लिमिटेड (डीसीटीएल) *** मीट्रिक टन की क्षमता का एक संयंत्र स्थापित कर रहा है।
- ख. इस तथ्य से पाटन को उचित नहीं ठहराया जा सकता कि संबद्ध वस्तुओं की मांग भारतीय उत्पादकों की क्षमता से अधिक है।
- ग. घरेलू उद्योग से खरीद करना उपभोक्ताओं के हित में है क्योंकि घरेलू उद्योग भारत में उपभोक्ताओं के हित के लिए काम करेगा।
- घ. सार्वजनिक हित केवल उपभोक्ता उद्योग तक ही सीमित नहीं है और इसमें आवेदक का हित और अंततः आम जनता का हित भी शामिल है।
- ङ. विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी उपायों को लगाना जारी रखना घरेलू उत्पादकों के हित में है।

- च. यह उपभोक्ताओं के हित में है कि एक ऐसा प्रतिस्पर्धी आवेदक हो, जो उचित कीमत के आयातों की प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम हो।
- छ. भारत को विनिर्माण की महाशक्ति बनाने के उद्देश्य के लिए घरेलू विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना अनिवार्य है।
- ज. पाटनरोधी शुल्क उद्योग के लिए सुरक्षा नहीं है, बल्कि देश में निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा लाने का एक साधन है।
- झ. *रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि राष्ट्र का उद्देश्य भारत को आधुनिक और अत्यधिक औद्योगिक और शक्तिशाली राज्य बनाना होना चाहिए।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

118. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या सिफारिश किया गया पाटनरोधी शुल्क शुल्क लगाना जनहित के खिलाफ होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के रिकार्ड और हितों पर सूचना के विचार पर आधारित है।
119. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, ताकि वे वर्तमान समीक्षा जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान कर सकें, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों की परस्पर अदला-बदली, स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने के चलते उत्पन्न हुई नई स्थिति को समायोजन करने में तेजी लाने अथवा विलंब करने वाले कारकों के संबंध में सूचना की मांग की।
120. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी, जिसे इस समीक्षा जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। केवल घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है। प्रयोक्ता उद्योग ने न तो आर्थिक हित प्रश्नावली दाखिल की है और न ही प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है।
121. यह नोट किया जाता है कि सामान्य रूप से पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं के द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनः स्थापना की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने से विचाराधीन उत्पाद के कीमत स्तरों के साथ-साथ भारत में संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके निर्मित कि गए अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों के जारी रहने से घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सकेगा जो संबद्ध देशों से कम कीमत के आयातों के चलते हो सकती है और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता को बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
122. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विगत में पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने के कारण भारतीय उद्योग के लिए अनुकूल बाजार स्थिति बनी है। आर.के. सिंथेसिस ने उपायों के लागू होने के बाद अपने संयंत्र की स्थापना की है।

रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि एक अन्य उत्पादक, दीपक केम टेक लिमिटेड ने अपना संयंत्र स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

123. यह भी दावा किया गया है कि देश में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग और आपूर्ति के बीच अंतर होने से पाटन को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, उपायों के लागू होने से आयातों पर प्रतिबंध नहीं होगा और आयात जारी रहेंगे।
124. जहां तक डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का संबंध है, यह नहीं माना जा सकता है कि उपभोक्ताओं का प्रचालन केवल इसलिए अव्यवहारिक हो जाएगा कि शुल्क लगाए जाने से पाटन को रोका जाता है और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल होती है। पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य ही घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर प्रदान करना है, जिससे कि वे निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें और बाजार में आपूर्ति को जारी रख सकें।
125. उपभोक्ताओं ने संबद्ध और असंबद्ध देशों से आयात किया है। घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक और डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी उपायों के प्रभाव के संबंध में अतिरिक्त सूचना प्रदान की है। यह देखने में आया है कि प्रयोक्ता उद्योग के लिए प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

क्र. सं.	डाउनस्ट्रीम उत्पाद का नाम	यूओएम	उत्पाद की कीमत	मानक प्रति कि. ग्रा.	पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव	प्रभाव % में
1	एमिनो डिफेनिलमाइन	रु./ कि. ग्रा.	***	***	***	0.83%
2	सोडियम मर्कैप्टो बेंजोथियाज़ोल	रु./ कि. ग्रा.	***	***	***	0.16%
3	बेंजोथियाज़ोल	रु./ कि. ग्रा.	***	***	***	0.27%
4	ट्राइमेथिल डाइहाइड्रोक्विनोलिन	रु./ कि. ग्रा.	***	***	***	0.38%

ठ. प्रकटीकरण के उपरांत टिप्पणियां

ठ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

126. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के लिए निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. जिलिन रिसुन ने जांच की अवधि के दौरान केम्पर एनर्जी पीटीई लिमिटेड को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। यह तथ्य कि भारत को वस्तुओं का बाद में निर्यात जांच की अवधि के बाद हुआ, जिलिन रिसुन को व्यक्तिगत पाटन मार्जिन से अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए।
- ख. आवेदन में अधिकांश अपेक्षाएं शामिल नहीं थी जैसे कि संबद्ध देशों में कुल और सरप्लस क्षमता तथा यह औचित्य कि पाटनरोधी शुल्क वापस लेने के उपरांत भारतीय बाजार को निर्यात के लिए एक गंतव्य स्थान के रूप में क्यों चुना जाएगा।

- ग. कोई भी कीमत संबंधी कमी अथवा गिरावट नहीं है क्योंकि आवेदक और उत्पादक ऐसी फार्मूला-आधारित कीमत के निर्धारण के मॉडल पर आधारित अनुबंधों के तहत एनिलीन की बिक्री करते हैं जिसमें कि बेंजीन की प्रचलित लागत पर एक स्प्रेड लगाया जाता है।
- घ. प्राधिकारी ने प्रयोक्ता के इस अनुरोध पर विचार नहीं किया है कि शुल्क का प्रभाव *** है।
- ड. आवेदक प्रयोक्ता की मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने में संरक्षण का उपयोग नहीं कर रहा है। अतः शुल्क का विस्तार करके संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।
- च. क्षमता में किसी भी वृद्धि के बिना पीयूसी की मूल्यहास लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- छ. आवेदक ने पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना का दावा करने के लिए पाटन अथवा क्षति के जारी रहने को दर्शाने के लिए जांच की अवधि के बाद कोई डेटा प्रदान नहीं किया है।

ठ.2. आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

127. आवेदक द्वारा प्रकटीकरण के लिए निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: -

- क. वार्षिक आधार पर, जांच की अवधि के बाद चीन से आयातों में *** मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, जबकि अन्य देशों से कुल आयातों में *** मीट्रिक टन की कमी हुई है। आयातों पर पाटनरोधी उपायों को लागू किए जाने के बावजूद आयातों में वृद्धि हुई है।
- ख. अन्य देशों से आयात कीमत में *** रुपये प्रति मीट्रिक टन (वार्षिक) की वृद्धि हुई है, जबकि चीन जन गण के आयातों की कीमत में केवल *** रुपये प्रति मीट्रिक टन (वार्षिक) की वृद्धि हुई है।
- ग. जैसे ही संयंत्र ने उत्पादन करना पुनः शुरू किया, चीन के उत्पादक एक बार पुनः आक्रामक हो गए। अप्रैल से 24 दिसंबर (वार्षिक) की अवधि में अन्य देशों को किए गए निर्यातों की मात्रा *** मीट्रिक टन से अधिक है।
- घ. जांच के बाद की अवधि में चीन की कीमतें अन्य देशों की तुलना में भारतीय बाजार के लिए चुनिंदा रूप से कम रही हैं। चूंकि चीन के उत्पादकों ने संयंत्र बंद होने के कारण भारतीय बाजार में कुछ बाजार खो दिया था, अतः उन्होंने कम कीमतों के साथ भारतीय बाजार का लक्ष्य किया।

ठ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

128. प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोधों की जांच की है। यह देखने में आया है कि इनमें से अधिकांश अनुरोधों में उन तर्कों और प्रति तर्कों की पुनरावृत्ति की गई है जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में उनका आवश्यकता के अनुसार समाधान किया गया है। संक्षिप्तता की दृष्टि से, प्राधिकारी ने इस प्रकटीकरण के उपरांत की जांच में ऐसे मामलों के संबंध में प्रतिक्रियाओं को दोहराने से बचने का प्रयास किया है। तथापि, प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोधों में पहली बार

उठाए गए किसी भी नए मामले के साथ ही पहले से संबोधित किए जा चुके, लेकिन प्राधिकारी द्वारा आगे की जांच के लिए आवश्यक समझे गए मामलों की जांच की जाती है और उनका समाधान किया जाता है।

129. प्रयोक्ता उद्योग की इस टिप्पणी पर कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव *** है, प्राधिकारी ने यह पाया कि प्रयोक्ता उद्योग ने वर्तमान जांच के दौरान न तो प्रश्नावली का उत्तर दिया है और न ही आर्थिक हित प्रश्नावली दाखिल की है। प्रभाव के संबंध में उनके अनुरोध में कोई मात्रात्मक आकलन किए जाने का अभाव है। जबकि प्राधिकारी का यह मानना है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से कीमतों में वृद्धि हो सकती है, यह निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा भी सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से जब पाटन जारी रहे।
130. इस टिप्पणी पर कि आवेदक मांग को पूरा करने के लिए क्षमताओं का विस्तार नहीं कर रहा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है। लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई है, यहां तक कि यह नकारात्मक हो गया है, जिससे उद्योग की निवेश आकर्षित करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग द्वारा अपस्ट्रीम उत्पाद की क्षमता का विस्तार किया जाना भी यह दर्शाता है कि अपस्ट्रीम उत्पादन और बिक्री डाउनस्ट्रीम प्रचालनों की तुलना में अधिक व्यावहारिक थे। इसके अलावा, उत्पादन का विस्तार करने में असमर्थ होना आवेदक को पाटनरोधी उपायों की मांग करने से रोकना नहीं है।
131. जिलिन रिसुन की इस टिप्पणी पर कि उसने जांच अवधि के दौरान केम्पर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की और इसलिए उसे व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान किया जाना चाहिए, प्राधिकारी पुनः इस बात को कहते हैं कि केम्पर एनर्जी लिमिटेड (निर्यातक) ने उत्पादक द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है। व्यक्तिगत मार्जिन का निर्धारण करने के लिए डेटा पूर्ण होना एक मूलभूत अपेक्षा होती है और डेटा न होना निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। चूंकि निर्यात की श्रृंखला पूरी नहीं है, अतः प्राधिकारी उत्पादक के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है।
132. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों के संबंध में कि घरेलू उद्योग को मूल्य दमन का सामना नहीं करना पड़ा है, यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2023-24 (पीओआई) में, जांच की अवधि में बिक्री की लागत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई है, बिक्री मूल्य में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई है। क्षति अवधि के दौरान, बिक्री मूल्य में वृद्धि की दर बिक्री की लागत में वृद्धि से कम है। इसलिए, आयातों ने क्षति अवधि के दौरान बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है।
133. इस टिप्पणी पर कि क्षमता में वृद्धि के बिना मूल्यहास लागत में वृद्धि हुई है, प्राधिकरण ने नोट किया कि उत्पादक के आंकड़ों की जांच की गई है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान एनिलीन संयंत्र में एक नया टरबाइन जोड़ा था। इस प्रकार एनिलीन की कुल लागत में मूल्यहास लागत का हिस्सा केवल ***% है और घरेलू उद्योग की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के बारे में निष्कर्षों को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करता है।

ड. निष्कर्ष

134. दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना, तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसा कि उपरोक्त निष्कर्षों में दर्ज किया गया है, तथा घरेलू उद्योग के साथ पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है:
 - i. विचाराधीन उत्पाद एनिलीन है जिसे एनिलीन तेल के रूप में भी जाना जाता है।
 - ii. आवेदक द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

- iii. यह आवेदन गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है तथा आर.के. सिंथेसिस ने इस आवेदन का समर्थन किया है।
- iv. वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने एक पूर्ण प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है और पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए सूचना पर विचार किया गया है।
- v. जिलिन रिसुन कॉनेल केमिकल कंपनी लिमिटेड ने निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए पूर्ण सूचना प्रदान नहीं की है। अतः व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है।
- vi. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और यह देखा गया है कि मार्जिन सकारात्मक है। उत्पाद का पाटन जारी रहा है।
- vii. आधार वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-2022 में निरपेक्ष रूप से संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है, वर्ष 2022-2023 में और वृद्धि हुई है तथा जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। क्षति अवधि में आयातों में वृद्धि हुई है।
- viii. आयात कीमत आवेदक की बिक्री कीमत से कम है जिसके चलते सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।
- ix. क्षति अवधि के दौरान, बिक्री कीमत में वृद्धि की दर बिक्री की लागत में वृद्धि की दर से कम है। घरेलू उद्योग की कीमतें कम हुई हैं।
- x. घरेलू उद्योग की स्थिति पाटन के प्रति संवेदनशील है:-
 - क. घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्री आवेदक की मौजूदा क्षमता से कम रही है।
 - ख. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार अंश में गिरावट आई है। भारतीय उद्योग के बाजार अंश में भी गिरावट आई है।
 - ग. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभों में गिरावट आई है और यह जांच की अवधि में यह घाटे में परिवर्तित हो गया है।
 - घ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई है, जिससे उसकी पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है।
- xi. जांच में ऐसा कोई अन्य कारक नहीं दर्शाया गया है, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।
- xii. पाटनरोधी उपायों के समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है:-
 - क. जांच की अवधि के बाद संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि हुई है और सभी स्रोतों से कुल आयात में इसका अंश सबसे अधिक है। जांच की अवधि के बाद अन्य देशों से आयातों में गिरावट आई है। पाटनरोधी उपाय होने के बावजूद आयातों में वृद्धि हुई है।
 - ख. वानहुआ ग्रुप के मामले में घरेलू बिक्री क्षमता का केवल ***% है। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि संबद्ध देश में उत्पादक सरप्लस क्षमताओं के साथ काम कर रहे हैं।
 - ग. वानहुआ ग्रुप ने वर्ष 2021-22 में *** मीट्रिक टन की क्षमता वृद्धि होने की सूचना दी है।
 - घ. जांच अवधि के दौरान तीसरे देशों को निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डंप कीमतों तथा क्षतिपूर्ण कीमतों पर भी किया जाता है।

xiii. यह देखने में आया है कि शुल्कों का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।

xiv. देश में मांग और आपूर्ति में अंतर है। प्राधिकरण ने पाया कि मांग-आपूर्ति का अंतर डंपिंग को उचित नहीं ठहराता। उपाय लागू करने से आयात पर रोक नहीं लगेगी और आयात अनडंप कीमतों पर और गैर-विषय देशों से भी होता रहेगा।

ड. सिफारिशें

135. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लागू कानून के अनुसार वर्तमान कार्यवाही संचालित की गई थी। सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत रूप से सूचित कर दिया गया था और उन्हें पाटन, क्षति, कारणात्क संबंध, पाटन व क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और भारतीय उद्योग पर उपायों के प्रभाव सहित जांच के अंतर्गत मामलों पर सूचना प्रदान करने तथा अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। निर्णायक समीक्षा को देखते हुए, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि वर्तमान मामले में मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखना आवश्यक है।

136. इस प्रकार, प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के समान निश्चयात्मक शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश करना उचित और आवश्यक समझते हैं। अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के समान पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र सं	शीर्ष/ उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2921 41	एनिलीन	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड	36.90	मी. टन	अमेरिकी \$
2	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	ऊपर बताए गए संयोजन के अलावा कोई भी संयोजन	121.79	मी. टन	अमेरिकी \$
3	- वही -	- वही -	चीन जन. गण. को छोड़कर कोई अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई भी	121.79	मी. टन	अमेरिकी \$

ण. आगे की प्रक्रिया

137. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/ समीक्षा के विरुद्ध कोई भी अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****FINAL FINDING**New Delhi, the 22nd April, 2025**CASE NO. ADD (SSR)-03/2024****Subject: Final finding in the sunset review investigation of anti-dumping duty imposed on imports of Aniline from China PR.**

F. No. 7/10/2024 .– DGTR - Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “Rules”).

The Designated Authority (hereinafter referred to as “the Authority”) received an application from Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’ or the “the domestic industry”) seeking initiation of a sunset review for extension of the present anti-dumping duty imposed on imports of Aniline (hereinafter to be referred to as the “subject goods” or the “the product under consideration” or the “PUC”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The original anti-dumping investigation into imports of product under consideration from China was initiated by the Authority on 24th January 2020. Following a request by the applicant and a thorough preliminary examination, the Authority, through Notification No. 6/42/2019-DGTR, dated 12th June 2020, recommended imposition of provisional anti-dumping duty. Subsequently, the Ministry of Finance imposed provisional duties vide Customs Notification No. 20/2020-Customs (ADD) dated 29th July 2020.
2. Through final findings No. 6/42/2019-DGTR, dated 20th January 2021, the Designated Authority confirmed the preliminary finding and recommended imposition of measures for a period of 5 years. The Ministry of Finance imposed duties vide Notification No. 08/2021-Customs (ADD), dated 19th February 2021.
3. Thereafter a mid-term review was initiated on the request of the user industry to examine whether there is a need for continued imposition of anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from China PR. The Authority vide F. No. 7/25/2022 - DGTR dated 11th December 2023 concluded that there was a continued need for imposition of anti-dumping duty. The present measures are in force till 28th July 2025.

4. In terms of Section 9A (5) of the Act, any anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such an imposition. Further, Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

“any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry”

5. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
6. On the basis of *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, the Authority issued a public notice vide notification no. 7/10/2024- DGTR dated 24th September 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation. The investigation was initiated in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of the Rules to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and if there is a need for continued imposition of the anti-dumping duties.
7. The scope of the present review covers all aspects of the final finding no. 06/42/2019-DGTR dated 20th January 2021, and Notification No. 08/2021-Customs (ADD), dated 19th February 2021.

B. PROCEDURE

8. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
- a. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5.
 - b. The Authority issued a notification dated 24th September 2024, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the sunset review anti-dumping investigation concerning the imports of the product under consideration from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 24th September 2024 to the embassy of the subject country in India, the known producers, and exporters from the subject country, known importers and users in India, and the other interested parties, as per the email addresses made available by the domestic industry.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - e. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire was sent along with the names and addresses of the known producers/exporters of the subject country.
 - f. The Authority sent exporter's questionnaire to the known producers/ exporters in subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - g. The following producers and exporters have registered in the present investigation:

SN	Name of producer/exporters in the subject country
1	Wanhua Chemical (Singapore) Pte., Ltd.
2	Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
3	Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co., Ltd.
4	Kempar Energy Pte Ltd.
5	Connell Chemical Industry Limited Liability Company
6	Jilin Risun Connell Chemical Co., Ltd.
7	Risun Marketing Limited

h. The Authority sent importer's questionnaire to the known importers/users of the product under consideration in India calling necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

i. The following users/importers have registered in the present investigation.

SN	Name of users and importers
1	NOCIL Limited
2	Aarti Industries Limited

j. The Authority also sent copies of initiation notification to the known association and sought their comments.

k. Foreign producers, exporters and other interested parties who have not responded to the Authority, or have not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating.

l. The Authority issued an economic interest questionnaire to all the known producers and exporters, importers, and the domestic industry. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. Economic interest questionnaire was filed only by the domestic industry. None of the other interested parties have filed the economic interest questionnaire.

m. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

n. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2023 to 31st March 2024 (a period of 12 months). The injury period for the investigation will cover the periods 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.

o. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management (DG Systems) for transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The Authority received the data and has relied upon this data for the necessary analysis after due examination of the transactions.

p. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 13th March 2025 in hybrid mode. The parties that presented their views during the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with other interested parties and were advised to offer their rebuttals.

q. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

- r. Non-injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules.
- s. In accordance with Rule 8, the Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the domestic industry and the interested parties, which forms the basis of this final finding. The Authority verified the data and documents submitted by the domestic industry and the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- t. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- u. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present final finding on the basis of the facts available.
- v. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent the same is supported with evidence and considered relevant to the present investigation. The Authority will further examine the evidentiary documents submitted by the interested parties subsequent to the final finding, which will form the basis for conclusions of final findings.
- w. A disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which forms the basis of the present final finding was issued to the interested parties on 9th April, 2025. The post disclosure statement submissions received from the domestic industry and other interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Finding Notification.
- x. "****" in this final finding represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- y. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1US\$=Rs **83.69**.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

A.1 C.1 Submission of the other interested parties.

- 9. The other interested parties have not made any submissions with regards to the product under consideration and like article.

A.2 C.2. Submission of the domestic industry.

- 10. The domestic industry has submitted as follows with regards to the scope of the product under consideration and like article:
 - a. The scope of the product under consideration in the present investigation is the same as defined in the original investigation.
 - b. Aniline, also known as phenylamine or aminobenzene, is a fundamental aromatic amine.
 - c. The product under consideration is used in drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates
 - d. The product under consideration is classified under Chapter 29, under code 29214110.
 - e. There have been no developments in the product and the product produced by the domestic industry continues to remain like article to the imported product.

A.3 C.3. Examination by the Authority.

11. The present investigation is a sunset review investigation and the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. The product under consideration as defined in the original investigation is reproduced hereunder-

“3. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Aniline” which is also known as “Aniline Oil”. Aniline is a transparent, oily liquid and is a primary amine compound. Its colour transforms to light pale-yellow liquid when freshly distilled. Its colour darkens when exposed to light or air. Aniline is a basic organic chemical, essential for vital industries such as drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates.

4. The subject products are classified under Chapter Heading 29 under the code 29214110. The customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope”.

12. Having regard to the final findings notified by the Authority and examination of the submissions made in this investigation, the Authority confirms the same scope of the product under consideration as was notified earlier. The product under consideration is -

“Aniline which is also known as Aniline Oil”.

13. The product is classifiable under Chapter 29 under the customs code 29214110.
14. It is also noted that the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of subject investigation.
15. The Authority notes that the product produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject country in terms of chemical characteristics, product specifications, technical specifications, manufacturing process, and technology, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, the Authority notes that the product produced by the domestic industry are ‘like article’ to the product under consideration imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules and the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**A.4 D.1 Submission made by the other interested parties.**

16. The other interested parties have submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and standing:
- a. The data for supporter R.K. Synthesis for sales or performance has not been provided in the application.

A.5 D.2. Submission made by the domestic industry.

17. The domestic industry has submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and standing:

- a. The application was filed by Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited and is supported by R.K. Synthesis Limited. There are no other producers producing the product in the market during the period of investigation.
- b. Post imposition of anti-dumping duty, another domestic industry, R.K Synthesis Limited has established its plant for Aniline.
- c. Deepak Chem Tech Limited (DCTL) is setting up a capacity of *** MT of Aniline.

A.6 D.3. Examination by the Authority.

18. The Authority notes that the present application has been filed by Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited. Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited has certified that it has not imported the product under consideration.
19. The Authority also notes that post imposition of anti-dumping, another domestic producer, R.K. Synthesis, commenced its production during the injury period. The company has supported the application. R.K. Synthesis has installed a capacity of *** MT. The supporter has filed a support letter giving information regarding its installed capacity, production, domestic and export sales.
20. There is no other producer of Aniline in India in the period of investigation. Based on the information on record, it is seen that Deepak Chem Tech Limited (DCTL) has signed a memorandum of understanding (MoU) with Government of Gujarat for a capacity of *** MT of Aniline. The domestic industry has provided information that the production is likely to commence in 2027.
21. The interested parties have contended that the data of the supporter is not provided with the application. The Authority notes that the support letter filed by the supporter was subsequent to the filing of application and was made part of the non-confidential application circulated with the other interested parties. Further, the trends of the production and sales of the supporter were provided in the written submission.
22. The table below shows the production of the applicant and the supporter.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (Applicant)	MT	***	***	***	***
2	RK Synthetics Limited (Other Indian Producer)	MT	-	***	***	***
3	Total Indian Production	MT	***	***	***	***
4	Share of applicant	%	100%	90-100%	90-100%	90-100%

23. It is noted that the applicant is eligible domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules, even though standing within the meaning of Rule 5(3) is not required to be established in a sunset review initiated under Rule 23.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

A.7 E.1 Submission of the other interested parties.

24. The other interested parties have made following miscellaneous submissions:

- a. The applicant has not made a duly substantiated request for initiation of a sunset review investigation.
- b. While the applicant has added capacity four times for CNA and NB in the last 30 years, the applicant has not increased the production capacity of PUC in the last 30 years, i.e., since 1995.
- c. The applicant is a habitual user of trade remedy investigations and has enjoyed trade remedy protection for more than 20 years.
- d. The domestic industry has made baseless allegations regarding excessive confidentiality claimed in the exporter questionnaire response by exporters.

A.8 E.2 Submission made by the domestic industry.

25. The domestic industry has made following miscellaneous submissions:
 - a. The applicant has adhered to the requirements for the initiation of sunset review investigation.
 - b. While the capacity of Concentrated Nitric Acid and Nitro Benzene has been added based on the economic viability, selling Aniline remained unviable for the applicant because of the high influx of dumped imports into India from various sources in the past two decades.
 - c. The applicant has taken recourse of trade remedial measures for last 20 years because of dumped imports from various sources.
 - d. The shifting of dumping from one source to another has not allowed the applicant a chance to operate for a reasonably long period with reasonable profits. The applicant has remained vulnerable to dumping for all these years.
 - e. The producers and exporters from the subject country have claimed excessive and unwarranted confidentiality, which has prevented the applicant from making any meaningful comments.

A.9 E.3 Examination by the Authority.

26. As regards the submission of the parties that applicant has not provided duly substantiated application and has not adhered to the Trade Notice 03/2021, the Authority does not find basis in this assertion and holds that the applicant has provided duly substantiated application and has fulfilled all the requirements for initiation of the present sunset review investigation. The investigation was initiated based on sufficient *prima facie* evidence to justify the present sunset review investigation. The applicant has provided details of the capacity expansion with the exporters in China PR and third country export information in its application. Further, upon initiation all the interested parties were advised to submit their data and views. The same has been considered by the Authority to the extent relevant in the present final finding.
27. As regards the contention that the domestic industry is a habitual user of trade remedy measures and has enjoyed the benefits of the anti-dumping duty for more than 20 years, the Authority notes that the present investigation is the 1st sunset review investigation. There is no bar in law on the number of times domestic industry may seek redressal from unfair trade practices of the foreign producers/exporters nor is there any bar on the number of times anti-dumping duty can be imposed. The recommendations for the imposition of the anti-dumping duty are made only after investigation by the Authority and when the requisite legal requirements are met.
28. It has been contended by the other interested parties that the applicant has undertaken capacity expansion for the upstream products such as Concentrated Nitric Acid and Nitrobenzene but not for the product under consideration, despite there being a huge demand and supply gap. The domestic industry has claimed that since Aniline was being dumped in the Indian market, it was more viable for the applicant to sell Concentrated Nitric Acid in the domestic market than to consume it and produce Aniline. It is seen that the applicant in the present investigation has suffered financial losses

in Aniline. In terms of legal requirements, the inability to expand production in the past does not disentitle the applicant from seeking remedy from dumping. Further the Authority draws reference to the mid-term review investigation of Aniline from China wherein the following was observed: -

“39. The Authority also notes that in a situation where a business enterprise has an option to sell a product in the market or captively consumes the same, and the business enterprise decides to sell the input in the market, rather than captively consuming it shows relative viability of the decision. This at least shows that the production and sale of such input in the market was more profitable than consumption in downstream product.”

29. Considering the above reasons, the Authority is unable to accept the submission that the right and standing of the applicant to seek remedy is impaired on grounds of lack of capacity expansion in the past.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Submission by other interested parties

30. The other interested parties have made the following submissions with regard to the normal value, export price and dumping margin:
- a. The expiration of the 15-year transition period under Section 15 clearly establish that the “surrogate country” method is no longer valid, and normal value should now be determined based on Chinese prices and costs.
 - b. The WTO Appellate Body in the Fasteners case confirms that Paragraph 15(d) of China's Accession Protocol renders the provisions of Paragraph 15(a) invalid after December 11, 2016.
 - c. Jilin Risun Connell has sold the subject goods in India through intermediary exporter, Kempar Energy Pte Ltd. Thus, individual rates should be granted.
 - d. China PR should be granted market economy status and normal value calculation should be done as per Article 2 of the Anti-Dumping Agreement.
 - e. Annexure I to the rules provides a hierarchy for determination of normal value. The applicant has completely skipped the first two methodologies and has constructed normal value based on the cost of production.
 - f. There are significant imports from European Union and United States of America and these imports should be considered for determination of normal value.

F.2 Submissions by the domestic industry

31. The domestic industry has made the following submissions with regard to the normal value, export price and dumping margin:
- a. As per the Accession Protocol and practice of Authority, China should be treated as a non-market economy. Market economy treatment can be allowed only when the same is claimed and appropriateness thereof is demonstrated.
 - b. Chinese producers have participated, but none of the responding Chinese producers filed MET in the present investigation. The normal value should be determined as per Para 7 of Annexure I of the ADD Rules.
 - c. The price of the product has fluctuated significantly over the period of investigation. Any analysis between the import price and the price of the applicant based on weighted average will not be appropriate.
 - d. Participating Chinese producers have not exported comparable volume over each month of the period of investigation. Wanhua Group has not exported in [3] months over the period of investigation. Further, volume of imports in [4] months is very low.

- e. With fluctuation in the volume and price, a comparison with average normal value will not be appropriate.
- f. Connell Chemical Industry Limited Liability Company and Jilin Risun Connell Chemical Co. Ltd. should not be accorded a separate duty in the present investigation. These producers have not supplied product under consideration in the period of investigation.
- g. The export price from other countries to India is below the estimated cost of production. Therefore, the export price from United States of America and European Union cannot be considered as a basis for normal value.

F.3 Examination by the Authority

a. **Normal value.**

32. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling, and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

33. The response to Exporters' Questionnaire has been filed by the following producers/exporters:

- a. Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
- b. Wanhua Chemical (Singapore) Pte., Ltd.
- c. Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co., Ltd.
- d. Kempar Energy Pte Ltd.
- e. Jilin Risun Connell Chemical Co., Ltd.
- f. Risun Marketing Limited

34. The Authority notes the following relevant provisions with regard to the determination of normal value for China PR. Provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to the Anti- Dumping Rules are as under:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like

product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in a similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

“8. (1) The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization.”

35. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers / exporters in

China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment / supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters in China PR to provide relevant information in this regard.

36. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

37. The Authority notes that while the provisions of Article 15 (a)(ii) of China PR's Accession Protocol have expired with effect from 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure 1 of Anti-Dumping Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming MET status.

38. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR has filed the supplementary questionnaire response to rebut the presumptions as mentioned in para 8 of Annexure – I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure – I of the Rules.
39. It is noted that paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules stipulates three methods of calculating the normal value for non-market economies: (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must first be determined on the basis of the price or constructed value in a surrogate country, or the price of the exports from such country to other countries, including India.
40. At the stage of filing the application, the domestic industry submitted that the normal value for China PR should be constructed based on the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin.
41. The other interested parties have claimed that the normal value should be determined based on the export price from United States of America or European Union. The Authority holds that paragraph 7 of Annexure-I to the Rules provide a hierarchy which is required to be followed. It is seen that there are significant imports from non-subject countries. While the import volume from China PR is 52,869 MT, the next highest import volume is from European Union at 49,197 MT. European Union being a non-subject country with no anti-dumping measure in force and with import volume being quite significant, the CIF price from European Union is representative in nature. Further the exports from EU are meant for the Indian market and are occurring in comparable time span. In view of the above, the Authority has considered European Union as the appropriate market economy third country and determined the normal value in terms of para 7 of Annexure-I of the Rules. Since these prices are at CIF level, appropriate adjustments on various elements like ocean freight, marine insurance and other expenses have been made as per consistent practice for arriving at an ex-factory price. The normal value so calculated is mentioned in the dumping margin table.
- a. **Export Price.**
- i. **Wanhua Chemical Group Co. Ltd. (Exports to India by M/s Wanhua Chemical Group Co., Ltd., China PR (Producer), M/s Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co., Ltd., China PR (Trader), M/s Wanhua Chemical (Singapore) Pte., Ltd., Singapore (Trader), and M/s Kempar Energy Pte Ltd., Singapore (Trader)**
42. Wanhua Chemical Group Co. Ltd., is a limited company incorporated and registered under the Company Law of People's Republic of China. It is noted that during the POI, Wanhua Chemical Group Co. Ltd., China PR has sold *** of subject goods of invoice value RMB *** to India indirectly through two related exporters/traders namely, Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co., Ltd., *** and Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd. ***. It is further noted that Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co., Ltd., has further resold the same subject goods to India indirectly through Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd.
43. It is also noted that the out of total subject goods sold by the producer to Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd. ***, the exporter/trader has sold *** of subject goods directly to India, and rest was sold to India indirectly through another unrelated exporter/trader namely, Kempar Energy Pte.

Ltd., Singapore. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, port and other related expenses and inland transportation to arrive at export price at ex-factory level. The adjustments claimed by the exporter/producer have been accepted after desk verification, and the ex-factory export price so determined is shown in the Dumping Margin Table below:

ii. Jilin Risun Connell Chemical Co., Ltd

44. It has been claimed that Jilin Risun Connell Chemical Co., Ltd. (Jilin Risun) is a limited liability company (partially invested by capital from investment from Chinese Hong Kong, Chinese Macao and Chinese Taipei) established according to “P.R.C Corporate Law”
45. It has been claimed that during the POI, M/s Jilin Risun Connell Chemical Co., Ltd., has made only one transaction of *** of subject goods having invoice value of RMB *** to India indirectly through a related exporter/trader namely, Risun Marketing Limited. Risun Marketing Limited has further informed that its customer Kempar Energy Limited has issued the commercial invoice for resale of the shipment to India in April 2024 (Post POI period). Therefore, the shipment was not reported by Kempar Energy Limited. However, since no data has been made available by Kempar Energy Limited with regard to sales of subject goods purchased from Risun Marketing Limited, China PR to India, and chain of export sales to India is incomplete, Jilin Risun Connell Chemical Co., Ltd., has not been granted individual margin.

iii. Export prices for all non-cooperative producers/exporters from China PR.

46. The export price for other non-cooperative producers/exporters from China has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules, and the same is mentioned in the dumping margin table.
47. Based on the determination of normal value and export price as above, the dumping margin has been determined and is shown below.

SN	Particulars	Normal Value (USD/MT)	Net Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin	Dumping Margin
1	Wanhua Group	***	***	***	***	10-20%
2	Any other	***	***	***	***	25-25%

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK.

G.1. Submission of the other interested parties.

48. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:
- The production and capacity utilization of the domestic industry fell to a level which was extremely insufficient to meet the Indian demand.
 - The applicant has failed to provide evidence on the effect of subject imports on the economic parameters.
 - The price undercutting is negative in financial year 2020-2021 and the period of investigation. Thus, the imports had no effect on the prices of the applicant.
 - The demand-supply gap has enabled the applicant to sell subject goods at prices higher than the imports. The users are forced to buy at higher prices.

- e. There is no price effect of imports from China PR and import price from United States of America is lower than the import price from China PR.
- f. There is no price suppression or depression as the applicant and exporters sell the goods under contract based on formula- based pricing.
- g. Depreciation cost of the applicant has risen over to a dramatic level in the period of investigation without any increase in the capacity of the subject goods.
- h. The domestic industry has reduced their production and sales despite having the protection of anti-dumping duty and has not taken any steps to expand its capacities.
- i. It should be analyzed if increase in imports from other countries has caused injury to the domestic industry.
- j. The imports from China PR have increased by 8% whereas the overall demand in the market has increased by 65%.
- k. The decrease in domestic sale is due to the factors other than imports from China PR.
- l. Allowing return on capital employed at 22% by the Authority is inflated and not in accordance with the law.
- m. The domestic industry fails to address the critical factors like internal issues, global market conditions, raw material price fluctuations, COVID-19 and the Russia-Ukraine war, which has impacted the domestic industry.
- n. Wanhua was operating at reduced capacity due to scheduled maintenance and its plant was not completely shut down.

G.2. Submission of the domestic industry.

49. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:
- a. Imports from the subject country have continuously increased in absolute terms and in relation to Indian production and consumption.
 - b. Imports from subject country continuously increased with only exception being 2023-2024.
 - c. The decline in the imports in the period of investigation was attributable to the plant shutdown of Wanhua Group for some time. This has also resulted in increase in the imports from other countries into India.
 - d. Imports from subject country have shot up in the post period of investigation.
 - e. In the cumulative imports from all sources, the imports from China hold the highest shares in total imports.
 - f. The applicant is forced to sell below the import price in order to sell in the domestic market.
 - g. There is significant price suppression as the rate of increase in selling price is much below the rate of increase in cost of sales.
 - h. Despite anti-dumping duty being in force, the share of the applicant has remained much below its capacity.
 - i. The production of the applicant increased in 2021-2022, thereafter substantially declined in 2022-2023, when the imports from subject country were highest. The production in the period of investigation was lower than the base year and 2021-2022.
 - j. There are significant fluctuations in monthly price of the product under consideration, due to which any analysis between the import price and the price of the applicant based on weighted average will not be appropriate. There is a need for determination of monthly price undercutting, monthly dumping margin and monthly injury margin.
 - k. The difference between the highest monthly and the lowest monthly import price over the period of investigation was *** for China, *** for the applicant, *** in case of USA, *** in case of Netherland and *** in case of Belgium.

- l. Despite consistent increase in demand each year, the domestic sales of the applicant did not improve. During period of investigation the sales of the applicant improved only because it sold at losses.
- m. Applicant's sales are at a level which is significantly below what it can cater and what the demand in the market is.
- n. The market share of imports from subject country remained substantially high till financial year 2022-2023 and decreased in the period of investigation.
- o. The applicant holds only *** of the market share in the demand. Whereas, if operating at optimum capacity, the market share of the applicant could have been ***.
- p. The applicant has suffered losses in the period of investigation. Applicant's profit before interest and return on capital employed have turned negative in the POI.
- q. For determination of return on capital employed for NIP, the Authority should consider average return on capital employed during the 2020-21 and financial year 2021-22. This was the period when there was no dumping of the product in the domestic market and the applicant was able to sell the product at adequate remunerative prices.

G.3. Examination by the Authority.

50. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...*". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
51. The Authority has taken note of the various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis carried out by the Authority *ipso facto* addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.
52. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury.
53. The Authority has also examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
54. It has been contended by the interested parties that the claimed injury is due to imports from other countries, the Authority has examined the import volume and price from the other countries. It is seen that the large volume of imports has taken place from China, European Union and United States of America during the POI. The imports from European Union and United States of America are priced

in the similar level to the import price from China. It is also seen that the imports from China hold the highest share in the domestic market. It is also seen from the information on record that the imports from China declined in the period of investigation because of the plant shutdown/maintenance in China. The Authority has also examined the Post POI import data of Aniline, and it is noted that the volume of import from USA has substantially declined while import from subject country has significantly increased during the same period.

55. The interested parties have contended that 22% return on capital employed should not be considered for determination of non-injurious price. The domestic industry requested the Authority to consider the return earned by the domestic industry during the period when there was no dumping. The Authority notes that relevant guidelines in this regard are well laid down under Annexure III of the Anti-Dumping Rules. The Authority has consistently allowed 22% return on capital employed and as it does not see any justifiable reasons to deviate from its established practice, the same has been adopted in the present investigation as well.

G.3.1. Volume effect of the dumped imports

a. Assessment of demand/consumption

56. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, the supporter, and imports of Aniline from all sources.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Sales of the domestic industry	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	117	65	91
2	Sales of supporter	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	0	100	203	343
3	Subject country import	MT	47,900	65,135	76,705	52,869
4	Other countries import	MT	23,718	24,203	17,331	94,867
5	Total demand	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	123	111	172

57. It is seen that as compared to the base year 2020-2021, the demand for the product under consideration had increased in 2021-22, declined in 2022-23 and increased significantly again in the period of investigation.

b. Imports in absolute and relative terms

58. The information on volume of imports in absolute terms and relative terms over the injury period and in the period of investigation is as below.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Subject imports	MT	47,900	65,135	76,705	52,869
2	Other imports	MT	23,718	24,203	17,331	94,867
3	Total imports	MT	71,618	89338	94036	147736
4	Subject country import in relation to					
A	Indian Production	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	112	225	112

B	Indian Demand	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	111	144	64
C	Total Imports	%	***	***	***	***

59. It is seen that:

- The volume of subject imports in absolute terms has increased in 2021-2022 as compared to the base year 2020-21, further increased in 2022-2023 and declined in the period of investigation. This indicates a fluctuating trend in import volumes over the years.
- The imports from subject country increased in relation to Indian production till 2022-23 but declined in the period of investigation. Similar trend is seen for imports in relation to consumption and total imports.
- The imports from subject country remained substantially high in relation to the Indian production, Indian demand and total imports till 2022-2023.

G.3.2. Price effect of dumped imports

60. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Price undercutting

61. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports. The table below shows the price undercutting from the subject country on average basis during the injury period.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Selling price	₹/MT	***	***	***	***
2	Landed price	₹/MT	***	***	***	***
3	Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***
4	Price undercutting	%	***	***	***	***
5	Subject Countries	Range	30-40%	0-10%	0-10%	0-10%

62. It is seen that price undercutting has fluctuated over the injury period. The price undercutting is positive over the injury period.

63. The domestic industry has contended that there is significant fluctuation in the price of the product and there is a need for determination of monthly price undercutting. The table below shows the price undercutting on a monthly basis for the period of investigation.

64. Analysis of price undercutting on monthly basis for the period of investigation.

SN	Month	Imports in MT	NSR Rs/MT	Landed price Rs/MT	Price undercutting Rs/MT	Price undercutting %	Range (%)
1	Apr-23	***	***	***	***	***	20-30
2	May-23	***	***	***	***	***	0-10
3	Jun-23	***	***	***	***	***	0-10
4	Jul-23	***	***	***	***	***	Negative
5	Aug-23	***	***	***	***	***	Negative
6	Sep-23	***	***	***	***	***	0-10
7	Oct-23	***	***	***	***	***	Negative
8	Nov-23	***	***	***	***	***	Negative
9	Dec-23	***	***	***	***	***	Negative
10	Jan-24	***	***	***	***	***	Negative
11	Feb-24	***	***	***	***	***	10-20
12	Mar-24	***	***	***	***	***	0-10
13	Weighted Average	***	***	***	***	***	0-10

b. Price suppression / depression.

65. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as below.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
	Change	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	181	227	194
2	Net Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
	Change	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	161	167	140

66. It is seen that in the year 2021-2022, the cost of sales of the domestic industry increased by Rs *** per MT, the selling price has increased by Rs *** per MT. The cost of sales has further increased in 2022-23 by Rs *** per MT but the selling price increased only by Rs *** per MT. The rate of increase in selling price is at lower rate of increase in cost sales of the applicant.
67. In the year 2023-24 (POI), the cost of sales has declined in the period of investigation by Rs *** per MT, the selling price has declined by Rs *** per MT. Over the injury period, the rate of increase in selling price is lower than the increase in cost of sales. Therefore, the imports have suppressed the prices of the domestic industry in the market over the injury period.

G.3.4. Impact on economic parameters of the domestic industry.

68. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the

domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales.

69. Information on capacity, production, capacity utilization and domestic sales over injury period is as follows:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Installed capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	100	100	100
2	Capacity utilization	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	118	66	90
3	Production	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	118	66	90
4	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	117	65	91

70. It is seen that: -

- The capacity of the domestic industry has remained the same over the injury period.
- The capacity utilization of the applicant increased in 2021-22, declined in 2022-23 but increased again in the period of investigation. The capacity utilization has remained low.
- The production of the applicant increased in 2021-2022, declined in 2022-2023, but increased during the period of investigation. When seen over the injury period, the production of the domestic industry has declined.
- The domestic sales of the domestic industry increased in 2021-2022, declined in 2022-23 and increased in the period of investigation. The domestic sales have declined over the injury period.
- The production and the domestic sales of the domestic industry remained much below the existing capacity of the applicant.

b. Market share.

71. Information on market share of imports and the domestic industry over the period was as follows:

SN	Market share of	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	95	58	53
2	Supporter	%	***	***	***	***
	Trend	Index	0	100	224	245
3	Indian industry	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	97	62	58
3	Subject country import	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	110	143	64
4	Other countries import	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	83	66	233

72. It is seen that: -

- a. The market share of the domestic industry declined over the injury period.
- b. The market share of the Indian industry has also declined.
- c. The market share of imports from the subject country has continuously increased till 2022-2023 and declined during the period of investigation.
- d. The market share of imports from the non-subject countries has declined till 2022-2023 and increased during the period of investigation.

c. Profitability, cash profits and return on investment.

73. Information on profitability, return on investment and cash profits is as follows:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Profit/(Loss)	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	108	8	-2
2	PBIT	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	107	8	-1
3	Cash Profit	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	108	10	2
4	ROCE	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	89	7	-1

74. It is seen that the profits of the domestic industry have declined over the injury period and turned into losses in the period of investigation.

75. The domestic industry has earned profit before tax, cash profit and a positive return on capital employed till 2022-2023. The profit before interest, cash profit and return on capital employed reduced drastically in 2022-23 as compared to 2021-22 and became negative during the period of investigation.

d. Inventories.

76. Information on inventories is as follows:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Opening inventory	MT	***	***	***	***
2	Closing inventory	MT	***	***	***	***
3	Average inventory	MT	***	***	***	***
4	Trend	Index	100	81	91	90

77. It is seen that the average inventory of the domestic industry has declined over the injury period.

e. Employment, wages and productivity

78. Information on employment, wages and productivity over the injury period is as under:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	No of employees	Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	107	81	89
2	Salary & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	110	166	188
3	Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
	Trend	Index	100	118	66	90

4	Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	111	81	101

79. The productivity of the domestic industry has moved in line with production. While wages paid have increased, number of employees has declined.

f. Growth.

80. The information on growth is provided below: -

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	POI
1	Capacity	Y/Y	-	-	-
2	Production	Y/Y	18%	-44%	37%
3	Sales	Y/Y	17%	-45%	40%
4	Market share	Y/Y	-4%	-41%	-2%
5	Profit/loss	Y/Y	8%	-92%	-124%
6	Cash profit	Y/Y	8%	-91%	-78%
7	ROCE	Y/Y	-11%	-92%	-117%

81. It is seen that the applicant has recorded negative growth in price parameters.

g. Ability to raise capital investment.

82. It is seen that there is demand and supply gap in the country. It is noted that the profitability and return on capital employed of the domestic industry has declined. The domestic industry was earning losses during the period of investigation. Therefore, the ability to raise capital investment is adversely impacted.

h. Margin of dumping

83. It is seen that there is continued dumping of the subject goods in India from China PR, and dumping margin is more than *de-minimis* and significant.

H. CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

84. As per the Rules, the Authority is required to, inter alia, examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the Rules could have contributed or likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries.

85. It is seen that there were imports above *de-minimis* limits from other sources including European Union and United States of America. The Authority has compared the monthly import price from European Union and United States of America and China PR, and finds that import price from USA and EU is at similar level to that from China during the POI.

b. Contraction in demand and / or change in pattern of consumption.

86. The demand for the product under consideration has increased over the injury period. Further, the demand is likely to increase more in future.

c. Trade restrictive practices.

87. The Authority notes that there is no trade restrictive practice.

d. Development of technology.

88. The Authority notes that information on record shows that technology for production of the product has not undergone any change.

e. Export performance.

89. The domestic industry has not exported the product and therefore, the export performance cannot be a cause of injury.

f. Performance of other products.

90. The Authority has considered the data relating to the performance of the product under consideration only. Therefore, performance of other products produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN.

91. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The non-injurious price has been compared with the landed price of the product under consideration from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials and utilities and best utilization of production capacity has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses and/or assets have been excluded from the cost of production and/or non-injurious price. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) deployed for the product under consideration has been allowed for recovery of interest, corporate tax, and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

SN	Particulars	NIP	Landed price	Injury margin		
		\$/MT	\$/MT	\$/MT	%	Range
1	Wanhua Group	***	***	***	***	0-10%
2	Any other	***	***	***	***	10-20%

J. LIKLIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

J.1. Submissions made by other interested parties.

92. The other interested parties have made the following submissions with regard to likelihood:
- The applicant has stated that Wanhua Chemicals has expanded the capacity of Aniline without disclosing that the company has also expanded the downstream Methylenediphenyl Diisocyanate (MDI) capacity, where Aniline is used captively.
 - In the sunset review, the focus of the entire investigation is on the likelihood of injury and not the present level of dumping and injury.

- c. The applicant has not provided the post period of investigation data to indicate continuance of dumping or injury being caused to it, in order to claim likelihood of recurrence of dumping and injury.
- d. The imports from China PR have increased marginally from 2020-2021 to POI and therefore, there is no likelihood of recurrence of injury to the domestic industry on account of imports from the country.
- e. The applicant has not submitted any evidence about the availability of surplus capacity with the Chinese exporters.
- f. The likelihood of dumping and injury should be assessed as per the rigours under Article 11.3 of the Anti-dumping Agreement.
- g. The claim that Wanhua Group has undertaken expansion in 2022 is incorrect. In reality, the expansion undertaken is not significant. The majority of the production is intended to be consumed internally in production of MDI.

J.2. Submission made by the domestic industry.

93. The domestic industry has made the following submissions with regard to likelihood:
- a. Despite measures in force, the imports subject country is coming at dumped prices.
 - b. Imports from subject country have increased continuously despite measures in force.
 - c. Producers in China have expanded their capacities despite there being surplus demand in the country. With the expiry of measures, there is a likelihood of further increase in imports.
 - d. The capacity addition by Wanhua Group is of annual output of *** tons. This addition in itself is *** larger than the current Indian Capacity.
 - e. The response of the Wanhua group itself reinstates the fact that the capacity expansion undertaken is to increase sales and particularly, exports sales to India. It can be seen that the producer has expanded capacity, and its shipments have increased sharply.
 - f. Wanhua Chemical Group has significantly expanded its capacity in 2022 with an annual output of *** tons of Aniline.
 - g. The exporters in the China are exporting significant volumes at dumped and injurious prices in third countries.
 - h. Jilin Risun Connell Chemical Co., Ltd. has also set up capacities after the imposition of anti-dumping measures in the original investigation.

J.3. Examination by the Authority

94. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of the product under consideration from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
95. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the Rules and other relevant factors brought on record by the interested parties.
96. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration, viz.

- a. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
- b. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
- c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports; and
- d. Inventories of the article are being investigated.

97. The Authority has, *inter alia*, considered the above requirements and following parameters in order to determine whether dumping is likely to recur in the event of cessation of anti-dumping duty, and if so, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry. Additionally, the Authority has examined all the relevant information brought on record by the domestic industry and the other interested parties.

a. Rate of increase of dumped imports into India indicating likelihood of increased importation.

98. The table below shows the information regarding imports from the subject country.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Subject country import	MT	47,900	65,135	76,705	52,869
2	Total demand	MT	***	***	***	***

99. It is seen that the volume of imports from the subject country has increased. The imports declined in the period of investigation. Wanhua Group has also submitted that production was suspended on its plant in the period of investigation for some time. In the immediately three preceding years to the period of investigation, exports of Wanhua Group amounted to 30% of total imports into India. The Authority notes the submission of the domestic industry that the imports have increased again in the post period of investigation. The imports from subject country hold the highest share in the total imports from all sources.

100. The Authority has additionally examined the post period of investigation data with respect to imports. It is seen that the imports in the post period of investigation have seen a sharp increase in the volume from China PR. While the imports from China have increased, the imports from other countries have declined. The increasing imports from China when measures are in place, shows the likelihood of further increase if the duties are allowed to expire.

SN	Particulars	UOM	POI	Apr to Dec 24 (A)	Change
1	Imports from China	MT	52,869	92,604	39,735
2	Imports from European Union	MT	49,197	68,608	19,411
3	Imports from USA	MT	45,334	8,794	-36,540
4	Total imports from other countries	MT	94,867	82,156	-12,711

Source – Post period of investigation data as per DGCI&S published data.

101. The table below shows the information regarding import price from China and other countries in the post period of investigation. It is seen that while the import price from China as well as other countries has increased, the increase in the import price from China is significantly lower than the import price from other countries.

SN	Particulars	UOM	POI	Apr to Dec 24 (A)	Change
1	Imports from China	Rs/MT	1,20,874	1,33,734	12860
2	Imports from other countries including EU & USA	Rs/MT	1,23,271	1,42,263	18992
3	Difference	Rs/MT	2,397	8529	6132

Source – Post period of investigation data as per DGCI&S published data.

b. Freely disposable capacity indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets.

102. The table below shows the information regarding capacity and domestic sales of the participating producers from China PR.

SN	Particulars	UOM	Wanhua Group	Jilin Risun
1	Capacity	MT	***	***
2	Domestic sales	MT	***	***
3	Domestic sales as % of capacity	%	***	***
4	Domestic sales as % of capacity	Range	30-40%	20-30%

103. It is seen that the capacity of both the participating producers is significantly higher than their domestic sales. The domestic sales are only *** of the capacity in China PR in case of Wanhua Group. This indicates that the producers are operating with surplus capacities.

c. Capacity expansion.

104. The domestic industry has additionally provided information that the Wanhua group has undertaken capacity expansion and added further capacity of *** tons. The other interested parties have contended that the capacity addition is for production of MDI, a downstream product. The Authority has taken note of the exporter questionnaire response submitted by the participating producers.

105. It is seen that Wanhua group has reported a capacity increase of *** MT in the year 2021-22. With regard to another producer and exporter, it is noted that M/s, Jilin Risun has started producing the product from the year 2022-23, and has unutilized capacity of more than *** during the POI.

106. It is therefore considered that the producers in the subject countries have expanded capacities.

d. Third country dumping

107. It is seen that Wanhua Chemical Group Co., Ltd. has reported third country exports only to its related party, Wanhua Chemical (Singapore) Pte., Ltd. Wanhua Chemical (Singapore) Pte., Ltd has not provided information on its third country exports. Therefore, in the absence of information, the Authority has relied on trademap data.

108. Information with respect to third country dumping is given below.

SN	Particulars	UOM	Quantity
1	Total exports	MT	***
2	Exports below normal value	MT	***
3	Exports below normal value	%	42%

109. It is seen that 42% of exports are below the normal value.

e. Third country injurious prices.

110. It is seen that Wanhua Chemical Group Co., Ltd. has reported third country exports only to its related party, Wanhua Chemical (Singapore) Pte., Ltd. Wanhua Chemical (Singapore) Pte., Ltd has not provided information on its third country exports. Therefore, in the absence of information, the Authority has relied on trademap data.

111. Information with respect to third country exports at injurious price is given below.

SN	Particulars	UOM	Quantity
1	Total exports	MT	***
2	Exports below NIP	MT	***
3	Exports below NIP	%	18%

112. It is seen 18% of exports are below NIP.

f. Third country prices attractiveness.

113. It is seen that Wanhua Chemical Group Co., Ltd. has reported third country exports only to its related party, Wanhua Chemical (Singapore) Pte., Ltd. Wanhua Chemical (Singapore) Pte., Ltd has not provided information on its third country exports. Therefore, in the absence of information, the Authority has relied on trademap data.

114. Information with respect to price attractiveness is given below.

SN	Particulars	UOM	Quantity
1	Total exports	MT	***
2	Exports below Indian prices	MT	***
3	Exports below Indian prices	%	40%

115. It is seen that 40% of the exports to third countries are priced below the export price to India. It is therefore seen that there in event anti-dumping measures are revoked, there is a likelihood of diversion of exports to India.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

Submission of the other interested parties.

116. The other interested parties have made following submissions on Indian industry interest:

- a. There is a demand and supply gap in India which is forcing the users to import.
- b. The imposition of 10% of duty will reduce the overall profitability by ***.
- c. DCTL will commence production in 2027, i.e. for the next 2 years, the downstream users will still be facing the supply issue due to demand supply gap.
- d. The anti-dumping on subject goods has negatively impacted the users. The applicant has already benefitted from a 7.5% custom duty on imports in addition to the ADD, which provides the domestic industry with an added layer of protection.
- e. The duty, if continued, will work against the goals of the "Atmanirbhar Bharat" initiative, which aims to foster self-reliance and support the growth of MSMEs.
- f. The increasing input costs of the downstream producers undermines its growth.

Submission of the domestic industry.

117. The domestic industry has made been following submissions on Indian industry interest:
- a. Post imposition of anti-dumping duty, another producer, R.K. Synthesis has set up a plant in India. Deepak Chem Tech Limited (DCTL) is setting up a plant with a capacity of *** MT.
 - b. The fact that demand of the subject goods is higher than the capacity with the Indian producers does not justify dumping.
 - c. Procuring from the domestic industry is in the interest of the consumers as the domestic industry will work for the interest of the consumers in India.
 - d. Public interest is not limited to only consumer industry and also covers the interest of the applicant and ultimate public at large.
 - e. The continuation of the anti-dumping measures on imports of the product under consideration is in the interest of the domestic producers.
 - f. It is in the interest of consumers to have a competitive applicant capable of supplying the product to the consumers in competition to fair priced imports.
 - g. Encouraging domestic manufacturing activities is essential to make India the manufacturing powerhouse it aims to become.
 - h. Anti-dumping duty is not a protection to the industry, but rather a tool to bring fair market competition in the country.
 - i. Supreme Court in *Reliance Industries Ltd. Versus Designated Authority* recognized that aim of nation must be to create India as modern and highly industrialized and powerful state.

Examination of the Authority

118. The Authority considered whether imposition of the recommended anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of various parties including the domestic industry, foreign producers and consumers.
119. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present review investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the anti-dumping duty on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the continuation of the anti-dumping duty.
120. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties to this review investigation. Only the domestic industry has responded to the economic interest questionnaire. The user industry has neither filed an economic interest questionnaire nor filed user questionnaire response.
121. It is noted that the purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the continuation of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product under consideration as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the continuation of anti-dumping measures

would prevent the decline of the domestic industry that may ensue as a consequence of low-priced imports from the subject countries and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the product under consideration.

122. The Authority notes that the anti-dumping duties imposed in the past have led to the favorable market condition for the Indian industry. R.K. Synthesis has set up its plant post the imposition of measures. From the information on record, it is seen that another producer, Deepak Chem Tech Limited, has signed a MOU with Gujarat Government to set up its plant.
123. It has also been claimed that there is a demand and supply gap in the country. However, the Authority notes that the demand-supply gap does not justify dumping. Further, imposition of measures will not restrict imports and imports will continue to happen.
124. As regards the impact of anti-dumping duty on the downstream industry, it cannot be construed that the operations of the consumers would become unviable, merely because dumping is prevented by imposition of duty and fair competition is restored in the market. Anti-dumping duties are meant to create a level playing field for domestic producers, allowing them to compete fairly and continue supplying the market.
125. The consumers have imported from subject as well as non-subject countries. The domestic industry has additionally provided information on the impact of the anti-dumping measures on the public and downstream users. It is seen that impact is not significant for the user industry.

SN	Name of downstream product	UOM	Price of product	Norm per KG	ADD impact	Impact in %
1	Amino Diphenylamine	Rs/Kg	***	***	***	0.83%
2	Sodium Mercapto Benzothiazole	Rs/Kg	***	***	***	0.16%
3	Benzothiazole	Rs/Kg	***	***	***	0.27%
4	Trimethyl Dihydroquinoline	Rs/Kg	***	***	***	0.38%

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

L.1. Submissions by other interested parties.

126. The other interested parties have made the following comments to the disclosure statement:
 - a. Jilin Risun sold the subject goods to Kempar Energy Pte Ltd. during the period of investigation. The fact that the subsequent export of the goods to India occurred post-period of investigation should not disqualify Jilin Risun from individual dumping margin.
 - b. Application did not contain most of the requirements such as total and surplus capacity in subject countries, and justification as to why Indian market would be chosen as a destination for exports after withdrawal of anti-dumping duty.
 - c. There is no price suppression or depression as the applicant and producer sell Aniline under contracts based on formula-based pricing model wherein a spread is charged over the prevailing cost of benzene.
 - d. Authority has not considered the user submissions that the impact of duty is ***.
 - e. The applicant is not making use of the protection in enhancing its capacities to fulfil the user demand. Therefore, it should not be given protection by extension of duty.

- f. There has been a significant increase in the depreciation cost of the PUC without any increase in the capacity.
- g. The applicant has not provided any post period of investigation data to indicate continuance of dumping or injury being caused in order to claim likelihood of recurrence of dumping and injury.

L.2. Submissions by applicant.

127. The applicant has made the following comments to the disclosure statement: -

- a. On annualised basis, imports from China have increased in the post period of investigation by *** whereas total imports from other countries declined by ***. The imports increased despite imports attracting anti-dumping measures.
- b. Import price from other countries has increased by *** per MT whereas the import price China PR has increased only by *** per MT.
- c. As plant resumed production, Chinese producers once again became aggressive. The export volume to other countries in the period April to December 24 (annualised) are more than *** MT.
- d. Chinese prices in the post period of investigation have been selectively low for the Indian market as compared to other countries. As the Chinese producers lost some market in the Indian market due to plant shutdown, they targeted the Indian market with lower prices.

L.3. Examination by the Authority

128. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that the majority of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. For the sake of brevity, the Authority has refrained from repeating the examination of such issues in this post-disclosure examination. However, any new issues raised for the first time in the post-disclosure submissions, as well as those previously addressed but deemed by the Authority to require further examination, are examined and addressed hereinunder.
129. On the comment of the user industry that the impact of anti-dumping duty is ***, the Authority observes that the user industry has neither submitted a questionnaire response nor filed an economic interest questionnaire during the current investigation. Their submission on the impact lacks any quantified assessment. While the Authority acknowledges that the imposition of anti-dumping duties may lead to price increases, it also ensures fair market competition, especially when dumping continues to persist.
130. On the comment that the applicant is not expanding capacities to fulfil demand, the Authority notes that the domestic industry has continued to suffer injury. Profitability and returns on capital employed have declined, even turning negative, thereby affecting the industry's capacity to attract investment. The domestic industry's expansion of upstream product's capacity indicates that upstream production and sales were more viable than downstream operations. Furthermore, the inability to expand production does not preclude the applicant from seeking anti-dumping remedies.
131. On the comment of Jilin Risun that it sold the subject goods to Kempar Energy Pte Ltd. during the period of investigation and therefore it should be granted individual dumping margin, the Authority reiterates that Kempar Energy Limited (the exporter) has not provided any information with regard to the exports made by the producer. The completeness of data is a fundamental requirement for determining individual margins and the absence of data directly affects the determination of export

price and dumping margin. Since the chain of the exports is incomplete, the Authority is not in a position to determine dumping margin for the producer.

132. With regard to submissions made by the other interested parties that the domestic industry has not suffered price suppression, it is noted that in the year 2023-24 (POI), the cost of sales has declined in the period of investigation by *** per MT, the selling price has declined by *** per MT. Over the injury period, the rate of increase in selling price is lower than the increase in cost of sales. Therefore, the imports have suppressed the prices of the domestic industry in the market over the injury period.
133. On the comment that the depreciation cost had increased without increase in the capacity, the Authority notes that the data of the producer has been examined. It is seen that the domestic industry had added a new turbine to the Aniline plant during the period of investigation. As such the share of depreciation cost in the total cost Aniline is just *** and does not materially affect the conclusions regarding the deteriorating financial position of the domestic industry.

M. CONCLUSION

134. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the dumping, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:
- i. The product under consideration is Aniline which is also known as Aniline Oil.
 - ii. The product supplied by the applicant is a like article to the imported product from the subject country.
 - iii. The application has been filed by Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited and R.K. Synthesis has supported the application.
 - iv. Wanhua Chemical Group Co. Ltd. has filed a complete questionnaire response and the information has been considered for calculation of dumping margin.
 - v. Jilin Risun Connell Chemical Co., Ltd. could not provide complete information for its export chain for determination of export price. Therefore, individual dumping margin has not been determined.
 - vi. Considering the normal value and export price for the subject goods, dumping margin for the subject goods from the subject country has been determined and it is seen that the margin is positive. Dumping of the product has continued.
 - vii. The volume of subject imports in absolute terms has increased in 2021-2022 as compared to the base year 2020-21, further increased in 2022-2023 and declined in the period of investigation. The imports have increased over the injury period.
 - viii. The import price is below the selling price of the applicant resulting in positive price undercutting.
 - ix. Over the injury period, the rate of increase in selling price is lower than the rate of increase in cost of sales. The prices of the domestic industry are suppressed.
 - x. The position of the domestic industry is vulnerable to dumping: -
 - a. The production and the domestic sales of the domestic industry remained below the existing capacity of the applicant.
 - b. The market share of the domestic industry declined over the injury period. The market share of the Indian industry has also declined.
 - c. The profits of the domestic industry have declined over the injury period and turned into losses in the period of investigation.

- d. Profitability and return on capital employed of the domestic industry has declined which has impacted the ability to raise capital investment.
- xi. The investigation has not shown any other factor which could have caused injury to the domestic industry.
- xii. There is a likelihood of injury to the domestic industry in event of cessation of measures: -
- a. Imports from the subject country has increased in the post period of investigation and hold the highest share in the total imports from all sources. Imports from other countries have declined in the post period of investigation. The imports increased despite anti-dumping measures in place
- b. The domestic sales are only *** of the capacity in case of Wanhua Group. This indicates that the producers in the subject country are operating with surplus capacities.
- c. Wanhua group has reported a capacity increase of *** MT in the year 2021-22.
- d. A significant share of exports to third countries are also at prices below the dumped prices, and injurious price during the POI.
- xiii. It is seen that the impact of the duties will not be significant.
- xiv. There is a demand and supply gap in the country. The Authority notes that the demand-supply gap does not justify dumping. Imposition of measures will not restrict imports and imports will continue to happen at undumped prices, and also from non-subject countries.

N. Recommendations

135. The Authority notes that the present proceedings were conducted in accordance with the applicable law. All interested parties were duly notified and were granted adequate opportunity to provide information and present their views on the matters under investigation, including dumping, injury, causal link, likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury and impact of the measures on the Indian industry. Pursuant to the sunset review, the Authority has arrived at the conclusion that continuation of the existing anti-dumping duties is required in the present case.
136. The Authority, thus, considers it appropriate and necessary to recommend continuation of definitive duties equal to the figure indicated in Column 7 of the duty table below for a period of five (5) years on all imports of the subject goods from the subject country. Therefore, considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column 7 of the duty table given below is recommended to be extended on all imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

DUTY TABLE

SN	Heading/ subheading	Description of the goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	UOM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2921 41	Aniline	China PR	Any country including China PR	Wanhua Chemical Group Co., Limited	36.90	MT	US\$
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any combination other than the	121.79	MT	US\$

					combination specified above			
3	-do-	-do-	Any country except China PR	China PR	Any	121.79	MT	US\$

O. Further procedure

137. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

DARPAN JAIN, Designated Authority